



पत्र नहीं मित्र

देशबन्धु



नई दिल्ली, शुक्रवार, 5 सितम्बर, 2025 | वर्ष-18 | अंक -151 | पृष्ठ - 10 | मूल्य - 3.00 रुपए

केंद्र और राज्य सरकारें
मानवीय रुख अपनाएं

02

■ कांग्रेस कर्मचारियों के संघर्ष में सहयोग करने के...
■ दिल्ली-एनसीआर में अब खूनी हो रही रेलवे...

03

■ ट्रंप की टैरिफ नीति के बीच अमेरिकी सांसद से मिले...
■ अमेरिका को अखर सकती है किम, शी व पुतिन...

07

हर दिन मुस्कुराने की वजह
ढूँढे : जेनेलिया डिसूजा

10

सार संक्षेप

ममता बनर्जी ने विधानसभा में लगाए वोट चोर के नारे



नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को बंगाली प्रवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायक विपक्ष के नेता सुवेदु अधिकारी के जिलबन का विरोध कर रहे थे। स्पीकर विमान बनर्जी ने अव्यवस्था फैलाने के आरोप में भाजपा के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। घोष के अलावा चार अन्य भाजपा विधायकों को भी सदन से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, स्पीच के दौरान सीएम ममता ने मोदी चोर और वोट चोर के नारे लगाए।

पीएमएलए मामले में शिखर धवन ईडी के समक्ष पेश



नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप वनएक्सबेट से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के एक मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम धवन से पूछताछ कर रही है और इस मामले में उनका बयान दर्ज कर रही है। जांच एजेंसी को संदेह है कि धवन के कुछ विज्ञापनों और प्रचारों के जरिए इस ऐप से संबंध थे। इससे पहले ईडी ने इस मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रेना से पूछताछ की थी।

एनडीए विपक्ष को बदनाम करने की साजिश रच रहा : स्वामी प्रसाद मोर्य



लखनऊ। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मोर्य ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में दावा किया है कि यह भाजपा की साजिश है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने साजिश के तहत इसे अंजाम दिया, जिससे विपक्ष को बदनाम किया जा सके। बिहार बंद पर मोर्य ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपशब्द कहे, उसकी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई तस्वीरें सामने आई हैं। उन्होंने इस पूरी घटना को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित एक साजिश करार दिया, जिसका उद्देश्य विपक्ष को बदनाम करना है।

पुलिस ने पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया



सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। यह कार्रवाई 2 सितंबर को चितलनार थाना क्षेत्र के रावगुड़ा, किस्टावरम और आसपास के जंगलों में की गई। गिरफ्तार नक्सलियों में से एक पर 1 लाख रुपए का इनाम था। गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान माइवी राकेश, कमलू देवा, कुशराम बुधरा, मड़कम मुया और क्वासी पोन्जे के रूप में हुई है।

बारिश से हो रही तबाही पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

अवैध पेड़ कटाई का बदला ले रही प्रकृति

■ सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों को नोटिस भेजा

■ दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर भारत के कई राज्यों में आई बाढ़ और भूस्खलन पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए चार राज्यों को नोटिस जारी कर

‘प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटाई की गई है और यही हालिया आपदा का एक बड़ा कारण हो सकता है।’

जवाब दाखिल करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने जिन चार राज्यों को नोटिस जारी किया, उसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। कोर्ट ने इन राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी कर उनसे दो हफ्तों के भीतर जवाब



दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह



प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटाई की गई है और यही हालिया आपदा का एक बड़ा कारण हो सकता है।

बड़ी संख्या में लकड़ी के गट्टर बहते नजर आए

अदालत ने मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश के दृश्य देखे, जहां बड़ी संख्या में लकड़ी के गट्टर बाढ़ में बहते हुए नजर आए। यह अनियंत्रित पेड़ कटाई का संकेत है। वहीं, पंजाब में खेत और गांव तबाह हो गए हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी मामले की गंभीरता को रेखांकित किया। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर वे पर्यावरण

मंत्रालय के सचिव से बात करेंगे और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से भी संवाद स्थापित करेंगे।

प्रभावित राज्यों को इस पर ठोस जवाब देना होगा

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रभावित राज्यों को इस पर ठोस जवाब देना होगा कि बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और आगे ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए उनकी क्या योजना है।

बिहार बंद

भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडई पर भड़के लालू

बिहारियों को हल्के में ना लें गुजराती

पटना, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में खुले मंच से पीएम मोदी को मां की गाली देने के खिलाफ गुरावार को एनडीए ने आधे दिन का बिहार बंद बुलाया था। बंद के दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों से बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई की खबरें सामने आईं। अब इसको लेकर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। लालू ने एक्स पर लिखा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं-बहनों और बेटियों को गाली दो? गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें? यह बिहार है। बीजेपी के गुंडे-मव्वाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार



कर रहे हैं? क्या यह उचित है? शर्मनाक!

भाजपा के दिग्गज नेता सड़क पर उतरे

प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने ‘बिहार बंद’ बुलाया था। गुरुवार को राजधानी पटना समेत प्रदेशभर के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। इस दौरान, भाजपा के दिग्गज नेता भी सड़कों पर उतरे। पटना में भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं ने शहर भर के प्रमुख चौराहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और पार्टी के दिग्गज नेता संजय मयूख ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्षी की टिप्पणी की निंदा करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘इतनी बेशर्मी क्यों है? क्या आप प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करते हैं और आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है?’



देश में परिस्थितियां लोकतंत्र के अनुकूल नहीं: रेड्डी

पटना, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने आज कहा कि करीब 52 साल तक संविधान को सेवा करने के बाद आज मैं जिस पद के लिए खड़ा हूँ, वह सियासी नहीं संवैधानिक पद ही है। जस्टिस रेड्डी ने गुरुवार को पटना में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस समय देश में परिस्थितियां लोकतंत्र और संविधान के अनुकूल नहीं हैं और ऐसे समय में मेरे जैसे संविधान के जानकारों की भूमिका बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि मेरी पृष्ठभूमि सियासी नहीं है और मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। जस्टिस



संविधान की रक्षा के लिए उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना मेरी पृष्ठभूमि सियासी नहीं और मैं किसी भी दल का सदस्य नहीं

रेड्डी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के अलावा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कुछ और छोटी पार्टियों ने

समर्थन का वादा किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है उनका देश की जनता के बीच प्रतिनिधित्व करीब 63 प्रतिशत है और देश भर के भ्रमण के दौरान जिस तरह का समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसे देख कर अच्छे भविष्य की उम्मीद बन रही है। रेड्डी ने कहा कि युवा अवस्था से ही उनका रुझान राममनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा की तरफ था। उन्होंने कहा कि विचारधारा के स्तर पर बिहार में लोहिया ने बहुत से प्रयोग किए और कर्पूरी ठाकुर का उन्हें साथ मिला। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र की पृष्ठभूमि दो हजार साल से ज्यादा पुरानी है। इस धरती से भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और अशोक जैसे महान विभूति और शासक पैदा हुए।

जीएसटी दरों में बदलाव पर बोले चिदंबरम

सरकार को गलती सुधारने में 8 साल लगे

मद्रै, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को मद्रै एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी दरों में बदलाव पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी इस मुद्दे को उठाया था। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि कई नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने बार-बार इन गलतियों को सुधारने की मांग की थी। अब कम से कम सरकार ने यह मान लिया।



अर्थशास्त्रियों ने बार-बार इन गलतियों को सुधारने की मांग की थी

नेताओं ने उस समय किसी की बात नहीं सुनी। हमने संसद में भी कई बार इस मुद्दे को उठाया था। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि कई नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने बार-बार इन गलतियों को सुधारने की मांग की थी। अब कम से कम सरकार ने यह मान लिया।

जीडीपी का 0.05 प्रतिशत नुकसान हो सकता है : बर्नस्टीन

नई दिल्ली। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा घोषित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में व्यापक बदलावों का सार्वजनिक वित्त पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र पर केवल 18,000 करोड़ रुपए का राजकोषीय बोझ पड़ने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वित्त वर्ष 26 के लिए भारत के अनुमानित जीडीपी का केवल 0.05 प्रतिशत है।

कांग्रेस ने इथेनॉल नीति पर मोदी सरकार को घेरा

‘वोट चोरी’ की तरह ‘पेट्रोल चोरी’ की गई

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। कांग्रेस ने गुरुवार को इथेनॉल नीति पर बीजेपी और मोदी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि इथेनॉल से संबंधित सरकार की नीति से सीधे तौर पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों को फायदा हुआ और इस नीति के जरिए ‘वोट चोरी’ की तरह ‘पेट्रोल चोरी’ की गई है। पवन खेड़ा ने यह सवाल भी किया कि क्या लोकपाल 130वें



गडकरी के बेटों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया

संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने से पहले गडकरी और उनके बेटों पर लगे आरोपों की जांच करने का साहस करेगा ?

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, गडकरी के दोनों पुत्र इथनॉल को लेकर पिता की नीतियों के बल पर जबरदस्त कमाई कर रहे हैं। उनके पुत्रों की कंपनियों से सबसे ज्यादा इथनॉल की आपूर्ति हो रही है और पिता द्वारा बनाई गई पॉलिसी पर बेटे पैसा बना रहे हैं। उनकी दोनों कंपनियों का राजस्व 2024 में 55 करोड़ रुपए था जो बढ़कर अब 1361 करोड़ रुपए हो गया है।

उपलब्धि

यूनिवर्सिटी में आईआईएससी और कॉलेजों में हिंदू कॉलेज टॉप पर

एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी मद्रास फिर नंबर वन

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)-2025 रैंकिंग जारी की। शिक्षा मंत्रालय की इस रैंकिंग और ओवरऑल रैंकिंग और इंजीनियरिंग संस्थानों में आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान हासिल किया है। अगर मैनेजमेंट संस्थानों की बात करें तो यहां आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर है।

वहीं, कॉलेजों की रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज पहले स्थान पर है। मेडिकल कॉलेजों की रैंकिंग में नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) नंबर वन है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पर है। यह रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मंद प्रधान ने जारी की। इस रैंकिंग में बीते वर्ष की ही तरह इस साल भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। आईआईटी



मैनेजमेंट संस्थानों में आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मंद प्रधान ने जारी की रैंकिंग

मद्रास ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग

मणिपुर में शांति बहाली के लिए समझौते पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। मणिपुर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उग्रवादी संगठन कुकी-जो परिषद (केजेडसी) ने राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की निबाध आवाजाही के लिए खोलने तथा वहां तैनात सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने

गुरुवार को यहां बताया कि यह निर्णय कुकी-जो और उसके अधिकारियों के बीच सिलसिलेवार बैठकों के बाद लिया गया। गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार और कुकी राष्ट्रीय संगठन (के एनओ)-यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद एक समझौते एसओओ पर भी हस्ताक्षर किए गए।



जीएसटी सुधार को लेकर खरगे का सरकार पर वार, बोले

देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर लगा टैक्स

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को जीएसटी सुधार को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया था। इसीलिए हमने भाजपा के इस जीएसटी को ‘गम्बर सिंह टैक्स’ का नाम दिया।

खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, ‘कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में सरल और तर्कसंगत कर व्यवस्था के साथ जीएसटी 2.0 की मांग की थी। हमने जीएसटी के जटिल कंप्लायंस को भी सरल बनाने की मांग की थी, जिससे एमएसएमई और छोटे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए थे। 28 फरवरी 2005 को कांग्रेस-यूपीए सरकार ने लोकसभा में जीएसटी की औपचारिक घोषणा की थी। 2011 में ही जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जीएसटी बिल लेकर आए थे तब भाजपा ने इसका विरोध किया था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जीएसटी का विरोध किया था। आज यही भाजपा सरकार रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन का जश्न मनाती है, जैसे कि आम जनता से टैक्स वसूलकर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। इस मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया था। दूध-दही, आटा-अनाज, यहां तक कि बच्चों की पेंसिल-किताबें, ऑक्सिजन, इशोरेशन और



कांग्रेस-यूपीए सरकार ने लोकसभा में जीएसटी की औपचारिक घोषणा की थी। 2011 में ही जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जीएसटी बिल लेकर आए थे तब भाजपा और नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का विरोध किया था। आज यही भाजपा सरकार रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन का जश्न मनाती है: मल्लिकार्जुन खरगे

अस्पताल के खर्च जैसी रोज इस्तेमाल करने वाले वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाया गया। इसीलिए हमने भाजपा के इस जीएसटी को ‘गम्बर सिंह टैक्स’ का नाम दिया। कुल जीएसटी का दो-तिहाई यानी 64 प्रतिशत हिस्सा गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब से आता है, लेकिन अरबपतियों से केवल 3 प्रतिशत जीएसटी लिया जाता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स वसूली में 240 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और जीएसटी वसूली में 177 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।’

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आखिर में लिखा, ‘ये अच्छे हैं कि सरकार की 8 वर्ष देर से ही सही जीएसटी पर कुंभकर्णी नौद खुली और

जीएसटी 2.0 पर जयराम रमेश का सवाल, ‘क्या परिषद एक औपचारिकता रह गई है?’

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जीएसटी 2.0 को लेकर केंद्र सरकार की हालिया घोषणाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की वकालत करती रही है। मैं पूछता हूं कि क्या जीएसटी परिषद अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की वकालत करती रही है, जो दरों की संख्या घटाए, बड़े पैमाने पर उपभोग होने वाली वस्तुओं पर टैक्स की दरें कम करें, टैक्स चोरी, गलत वर्गीकरण और विवादों को न्यूनतम करें, इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर (जहां इन्पुट पर आउटपुट की तुलना में अधिक टैक्स लगता है) समाप्त करें, एमएसएमई पर प्रक्रियागत नियमों का बोझ कम करें और जीएसटी के दायरे का विस्तार करें। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कल शाम संवैधानिक निकाय जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बड़े ऐलान किए। हालांकि, जीएसटी परिषद की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2025 के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इसके निर्णयों की सारगर्भित घोषणा कर दी थी। क्या जीएसटी परिषद अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है? जयराम रमेश ने जीएसटी 1.0 पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, निजी खपत में कमी, निजी निवेश की सुस्त दरें और अंतहीन वर्गीकरण विवादों के बीच केंद्र सरकार को अब मानना पड़े है कि जीएसटी 1.0 अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुका है। दरअसल, जीएसटी 1.0 की डिजाइन ही त्रुटिपूर्ण थी और कांग्रेस ने जुलाई 2017 में ही इस पर ध्यान दिला दिया था, जब प्रधानमंत्री ने अपना यू-टर्न लेकर इसे लागू करने का निर्णय लिया था।



‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की वकालत करती रही है, जो दरों की संख्या घटाए, बड़े पैमाने पर उपभोग होने वाली वस्तुओं पर टैक्स की दरें कम करें, टैक्स चोरी, गलत वर्गीकरण और विवादों को न्यूनतम करें: जयराम रमेश, कांग्रेस नेता

उन्होंने जागकर रेट रेशनलाइजेशन की बात की है। सभी राज्यों को 2024-25 को आधार वर्ष मानकर 5 वर्षों की अवधि के लिए कंपनसेशन

दिया जाए, क्योंकि दरों में कटौती से उनके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है।’

सार संक्षेप

भाजपा की नौटंकी नहीं चलेगी, बिहार बंद पूरी तरह असफल : संजय यादव

पटना। सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की तरफ से बुलाए गए ‘बिहार बंद’ का प्रदेशभर में असर देखा गया है। पटना समेत कई शहरों में सुबह से ही एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और विरोध-प्रदर्शन किया। यह बंद कांग्रेस-राजद के मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में बुलाया गया। इसी बीच, राजद सांसद संजय यादव ने दावा किया कि यह बंद पूरी तरह से असफल रहा और बिहार की जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि राज्य में भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता भी मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। क्या उक्त बयान सनातन के मंत्रोच्चार हैं? अगर उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति कुछ कहे तो इसके लिए विपक्ष को दोषी ठहराया जाता है। यह दोहरापन अब नहीं चलेगा।

बिहार चुनाव में हार देखकर सरकार ने किया जीएसटी स्लैब में बदलाव : तनुज पुनिया

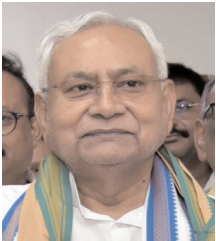
लखनऊ। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने केंद्र सरकार के जीएसटी स्लैब में बदलाव के फैसले को बिहार चुनाव से जोड़ा है। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएनएनएस से बातचीत में कहा कि यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मौजूदा समय में भाजपा को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हार की आशंका नजर आ रही है। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि वो बिहार इलेक्शन में हारने जा रहे हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने जीएसटी स्लैब में कटौती करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन, बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह फैसला आठ साल बाद क्यों लिया गया?

झूठ और फरेब की राजनीति करती है भाजपा : शक्ति सिंह गोहिल

उधम सिंह नगर। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए गए अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर भाजपा के हमलों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उस समय मंच पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ और फरेब की राजनीति करती है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि यह भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ‘बड़का झूठी पार्टी’ है। उन्होंने कहा कि न तो राहुल गांधी ने मंच से ऐसा कुछ बोला है और ना ही राहुल गांधी उस वक्त मंच पर थे, जिस वक्त की भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कह रहे हैं।

नीतीश ने सारण में 1203.81 करोड़ रुपए लागत की 27 योजनाओं का किया शिलान्यास

पटना, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सारण जिले में 1203.81 करोड़ रुपए लागत की 27 योजनाओं का शिलान्यास किया। श्री कुमार ने छपरा के रतनपुर बिन टोलिया स्थित कार्यक्रम स्थल से सारण जिला अंतर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित 1203.81 करोड़ रुपए लागत की 27 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत 545 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 400 / 220 / 132 के.बी. ग्रिड उपकेंद्र, छपरा एवं 132 के.बी. के संचरण लाइन का निर्माण कार्य, 60 करोड़ एक लाख रुपए लागत की एच.टी.एल.एस द्वारा रिफ़्बन्डरिंग का कार्य, 93 करोड़ 62 लाख रुपए लागत की एकमा – मशरख पथ का चौड़ीकरण कार्य एवं 41 करोड़ 66 लाख रुपए लागत की एकमा से डुमाइगढ़ तक पथ का चौड़ीकरण कार्य शामिल है।



मुख्यमंत्री नीतीश ने छपरा के जगदम कॉलेज से छेरा बिन टोलिया तक किये जा रहे सड़क के चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया

इसके अलावा इसके अंतर्गत 89 करोड़ 96 लाख रुपए लागत की एनओएच 19 के छूटे हुए छपरा सेक्शन पथ का चौड़ीकरण कार्य, 40 करोड़ 53 लाख रुपये लागत की खेरा बिन टोलिया पथ का चौड़ीकरण कार्य तथा सात करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से एकमा ग्रिड उपकेंद्र, शीतलपुर ग्रिड उपकेंद्र एवं मशरख ग्रिड उपकेंद्र में कुल पांच अदर 33 के.बी लाइन ‘बे के निर्माण कार्य सहित अन्य योजनाओं का शिलान्यास कार्य शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने विकासवात्मक योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने से पहले छपरा के जगदम कॉलेज से

खेरा बिन टोलिया तक किये जा रहे सड़क के चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण होने से छपरा में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिन टोलिया के पास बन रहे नए बस स्टैंड से रोड कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।

विदेशी सैन्य अताशे संग संवाद में बोले सेना प्रमुख द्विवेदी, रक्षा कूटनीति को मिली नई दिशा

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उषेन्द्र द्विवेदी ने नई दिल्ली स्थित मानेकशां सेंटर में विदेशी सैन्य अताशे से सीधा संवाद किया। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस वार्षिक विदेशी सेवा सैन्य अताशे ब्रीफिंग में 53 देशों के 67 रक्षा अताशे शामिल हुए



■ भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस वार्षिक विदेशी सेवा सैन्य अताशे ब्रीफिंग में 53 देशों के 67 रक्षा अताशे शामिल हुए

दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उभर रही चुनौतियों, भारत की सुरक्षा दृष्टि और भारतीय सेना की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यह रेखांकित किया कि भारत केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारतीय सेना का मानना है कि यह संवाद विभिन्न देशों के साथ न्यायालय ने शाह की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित आतंकवाद वित्तपोषण मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को अंतरिम जमानत पर तत्काल रिहा करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने शाह द्वारा जमानत की मांग करते हुए दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) की राय मांगी है। शब्बीर अहमद शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कार्लिन गोंजाल्विस ने मांग कि थी कि शाह ‘बेहद बीमार’ हैं, उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाह की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी

आतंकी वित्तपोषण मामला

सुप्रीम कोर्ट का अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को अंतरिम जमानत देने से इनकार

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित आतंकवाद वित्तपोषण मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को अंतरिम जमानत पर तत्काल रिहा करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने शाह द्वारा जमानत की मांग करते हुए दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) की राय मांगी है। शब्बीर अहमद शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कार्लिन गोंजाल्विस ने मांग कि थी कि शाह ‘बेहद बीमार’ हैं, उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।



इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक गैरकानूनी संगठन के अध्यक्ष के रूप में, वह इसी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और सबूतों से छेड़छाड़ करने या उन गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, जिनकी अभी जांच होनी बाकी है। न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत पर रिहाई की याचिका खारिज करते हुए कहा। ‘हालांकि अपीलकर्ता (शाह) पांच साल से हिरासत में है, लेकिन आरोप पहले ही तय हो चुके हैं और मुकदमा चल रहा है। अभियोजन पक्ष को और से गवाहों से पूछताछ न करने में कोई देरी नहीं हुई है।’ इसके अलावा, न्यायमूर्ति कौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शाह के खिलाफ गंभीर आरोपों और संबंधित मुद्दों की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए, घर में नजरबंदी की उनकी वैकल्पिक याचिका पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

थी कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक गैरकानूनी संगठन के अध्यक्ष के रूप में, वह इसी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और सबूतों से छेड़छाड़ करने या उन गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

प्राकृतिक आपदाओं पर मायावती की प्रतिक्रिया, बोलीं

केंद्र और राज्य सरकारें मानवीय रुख अपनाएं

लखनऊ, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से उत्पन्न हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इन आपदाओं के कारण पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम सहित कई राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में जान-माल और पशुधन की भारी क्षति हो रही है। साथ ही गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित किया है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को आने की खबरें और तस्वीरें संतोषजनक हैं और यह मानवता की भावना को दर्शाता है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की कि वे इस आपदा के समय अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएं और पीड़ितों की हर संभव सहायता करें। मायावती ने कहा कि सरकारों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि इन कठिन हालातों में जनता को भारी परेशानियों और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की मदद के लिए आम लोगों की तरफ से स्वयं आगे



बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा

मोतिहारी। बहुजन समाज पार्टी ने इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। बसपा ने पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने गुरुवार को पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी में कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार बसपा राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि न एनडीए और न ही महागठबंधन से कोई समझौता किया जाएगा। अनिल कुमार ने कहा कि जनता अब दोनों बड़े गठबंधनों से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा, ‘एनडीए और महागठबंधन दोनों ने जनता से सिर्फ झूठे वादे कर उठें ठगने का काम किया है। अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है और वह बदलाव बहुजन समाज पार्टी लेकर आएगी।’

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में बोले मोदी

आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारत के लोगों के प्रति संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को लेकर हमारी समान चिंताएं हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है।

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए, मैं प्रधानमंत्री वॉनग और सिंगापुर



आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं: नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री वॉनग की पहली भारत यात्रा पर, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये यात्रा और भी विशेष है, क्योंकि इस वर्ष हम दोनों देशों के

संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पिछले साल, मेरी सिंगापुर यात्रा के दौरान, हमने संबंधों को कॉन्फ्रेंसिव स्ट्रेटैजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। इस एक वर्ष में हमारे संवाद और सहयोग में गति और गहराई आई है। आज साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिड्लड रोडमैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल परंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। बदलते समय के अनुरूप, एडवांस मैनुफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, रिकॉलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा।

हड़ताल पर रहे हजारों सर्वे कर्मियों की सेवा समाप्त, अब होगी नई बहाली

पटना, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। बिहार सरकार ने हड़ताल पर बैठे विशेष सर्वे संविदा कर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी है। भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय ने स्पष्ट किया कि बार-बार की गई अपील और चेतावनी के बावजूद बड़ी संख्या में कर्मी इयूटी पर वापस नहीं लौटे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। भू अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय द्वारा पूर्व में प्रकाशित सूचना के माध्यम से हड़ताल/धरना प्रदर्शन कर रहे विशेष सर्वे संविदा कर्मियों से कर्तव्य पर वापस लौटने की अपील समाचार पत्रों, विभाग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस एवं निदेशालय के वेबसाइट के माध्यम से की गई थी। साथ ही इस हेतु पूर्व में पुनः एक और अंतिम अवसर देते हुये कर्तव्य पर वापस लौटने हेतु अवसर दिया गया था। निर्धारित तिथि एवं समय तक कुल 3295 संविदा कर्मियों द्वारा कर्तव्य पर वापस लौटकर कार्य किया जा रहा है। शेष सभी हड़ताल पर बने हुये संविदा कर्मियों की संविदा भू अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय द्वारा समाप्त कर दी गई है, जिसका आदेश निर्गत किया जा रहा है।

इसमें कहा गया है कि कटड़ा-बनिहाल खंड के 2025 में चालू होने के साथ, कश्मीर रेल गलियारा राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो जाएगा, जिससे यात्रियों की संख्या में वृद्धि और माल ढुलाई के नए रास्ते खुलेंगे। इस दोहरीकरण से सैनिकों और उपकरणों को ले जाने वाली सैन्य विशेष ट्रेनों का भी सुचारू संचालन संभव होगा।

दोहरीकरण परियोजना की योजना बारामुल्ला तक मौजूदा सिंगल लाइन पर भीड़भाड़ कम करने के लिए बनाई गई है।

- यात्रियों की संख्या में वृद्धि और माल ढुलाई के नए रास्ते खुलेंगे
- यह परियोजना सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है
- नए सिरे से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा

इसके लिए नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी।

बयान में आगे कहा गया है कि 73.50 किमी लंबी काजीगुंड-बडगाम



को एक नए सिंगल ब्राड-गेज ट्रैक के रूप में विकसित किया जाएगा और

कैपिटल ज़ोन

दिल्ली-एनसीआर में अब खूनी हो रही रेलवे की पटरियां

■ डॉ. कला अय्यर

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। भारत में रेलवे सबसे सस्ता, साधारण और सबसे सुरक्षित साधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि भारत के हर किसी राज्य में रेल की पटरियों का एक पूरा जाल बिछा ही हुआ होता है और ऐसा ही कुछ दिल्ली-एनसीआर में भी है। लेकिन

दिल्ली-एनसीआर की यह रेलवे की पटरियां अब खूनी हो रही हैं। दरअसल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) के एक डाटा के मुताबिक 2023 से 2025 जून अब तक, दिल्ली-एनसीआर की रेलवे पटरियों पर 1,321 शव पाए गए हैं। आरपीएफ के डाटा के मुताबिक 2023 और 2025 के बीच, ट्रेन की पटरियों पर मौत की संख्या में वृद्धि देखी गई है। 2023 में, रेलवे अधिकारियों ने रेलवे ट्रेकों से 533 शव उठाए, जबकि अगले वर्ष 2024 में, यह आंकड़ा बढ़कर 548 हो गया। वहीं इस

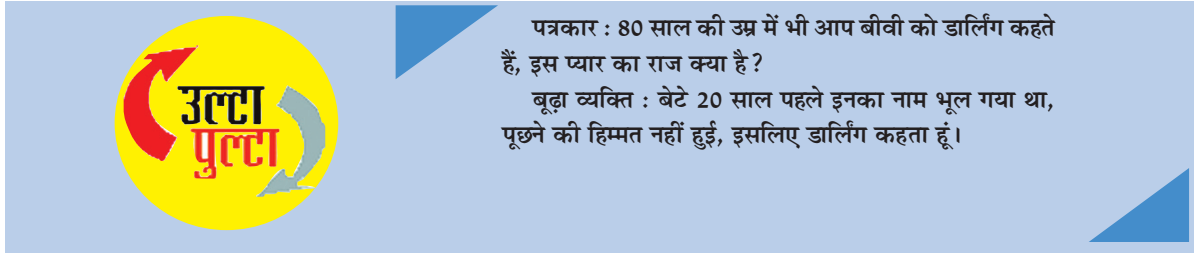


शॉर्टकट लेकर रास्ता टापने के अलावा, ट्रेन के दरवाजे के पास बैठे व्यक्ति किसी न किसी दुर्घटना की चपेट में आकर जान गंवाने में शामिल है : आरपीएफ

साल 2025 के जून महीने तक, 240 शव पहले ही मिल चुके हैं। आरपीएफ का यह भी कहना है कि इन घटनाओं में रेलवे के पांच स्ट्रेच सबसे अधिक जुड़े हुए हैं, जहां सबसे अधिक शव मिले हैं, जिसमें फरीदाबाद स्टेशन, दिल्ली शाहदारा जंक्शन, आदर्श नगर रेलवे स्टेशन, गुडगांव रेलवे स्टेशन और रोहतक रेलवे स्टेशन शामिल हैं।

आरपीएफ के अनुसार, इनमें से अधिकांश घटनाएं तब हुई जब कुछ व्यक्ति शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे थे। आरपीएफ का कहना था कि

उन्होंने कुछ लोग पकड़े भी हैं जो रेलवे ट्रेक के साथ-साथ चल रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उनका कहना था कि वह टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट ले रहे थे। वहीं रेलवे अधिकारियों ने यह बताया कि शॉर्टकट लेकर रास्ता टापने के अलावा, खुली ट्रेन के दरवाजे या गेट्स के पास बैठे व्यक्ति किसी न किसी दुर्घटना की चपेट में आकर जान गंवाने में शामिल हैं। वहीं उनका यह भी कहना था कि इसमें एक बहुत बड़ा कारण आमहत्या भी है। वहीं आरपीएफ ने बताया कि अब रेलवे पटरियों के अनधिकृत क्रासिंग पर अंकुश लगाने के लिए, विशेष रूप से पांच स्ट्रेचों पर, अधिकारियों ने रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत प्रवर्तन उपायों को तेज कर दिया है। जो रेलवे परिसर में पाए गए व्यक्तियों को दंडित करता है। वहीं क्रैकडाउन के हिस्से के रूप में, रेलवे पटरियों को पार करने के खतरों और फुट ओवरब्रिज और नामित मार्गों का उपयोग करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजित किया जा रहा है।



दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा

कांग्रेस कर्मचारियों के संघर्ष में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध

कांग्रेस ने रेलवे कर्मचारियों कि हक की लड़ाई में उनका साथ देने का दिया आश्वासन

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित हुए। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन कांग्रेस समर्थित इंटक का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश भर के 10 हजार से अधिक यहां राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे रेलवे कर्मचारियों सहित फेडरेशन पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं और आपके संघर्ष में साथ खड़े होकर कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जन नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की सोच हर देश के गरीब, एससी/एसटी और पिछड़ों की हर संभव मदद करने की रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आपके



केंद्र की गलत नीतियों के कारण रेलवे कर्मजोर बन संस्था बन गया है : देवेंद्र यादव, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

राष्ट्रीय अधिवेशन में निमंत्रण के लिए संदेश भेजा है जिसको पढ़कर सुनाया गया कि 1.3 मिलीयन रेलवे परिवार जो देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन सरकार ने आपको मजबूत बनाने के लिए कुछ नहीं किया है। रेलवे के निजीकरण और कर्मचारियों की कांटेक्ट पर भर्ती करके देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि रेलवे करोड़ों लोगों के सुविधाजनक

ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। कोविड के दौरान जान गंवाने वाले हजारों रेलवे कर्मचारियों को मुआवजा तक नहीं दिया गया। प्रभावित लोगों को मानवता के आधार पर मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। मौजूदा केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण रेलवे कमजोर बन संस्था बन गया है। हमें एकजुट होकर रेलवे कर्मचारियों की मांगों

जब राहत कैंपों को राहत की जरूरत पड़े तो जनता को क्या मदद मिलेगी : यादव

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में यमुना ने रौद्र रुप धारण कर लिया है और पानी खादर में उफान पर बह रहा है। उन्होंने कहा कि भयानक रुप ले रही यमुना से तटीय क्षेत्रों और सड़कों तक पहुंचे पानी से राहत दिलाने के लिए राहत कैंप पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाए है और जो राहत कैंप लगाए है उन्हे व्यवस्थित तरीके से नहीं लगाए गए है। शायद भाजपा सरकार के पास अनुभव की कमी रही। यही कारण है कि राहत कैंप कहा और किन सुविधाओं के साथ लगाने थे, वो कुछ राहत कैंपों में दिखाई नहीं दे रहा है। राहत शिविरों में खाने सहित दूसरी सुविधाओं की भारी कमी है। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे है। यादव ने कहा कि हमने 31 अगस्त को चेताया था कि बाढ़ से निपटने और लोगों को बचाने के जो काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में किए जा रहे है वो नाकाफी है, लेकिन सरकार ने दिल्ली कांग्रेस की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया जिसका हर्जाना दिल्ली की जनता भुगत रही है। यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत की घोषणा तो की है लेकिन सरकार द्वारा लोगों के लिए राहत कैंप को सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए टेंट लगाए है।

और सुविधाओं, निजीकरण और कांटेक्ट भर्तियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।

उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा अधिवेशन के आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी।

एनसीपी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष बनीं पूजा कुमारी

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी लगातार विभिन्न प्रदेशों में अपना विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में एनसीपी ने दिल्ली में राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा के रूप में पूजा कुमारी, अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय को नियुक्त किया है।

नियुक्ति पत्र देते हुए बृजमोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता, राकांपा ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि अधिवक्ता पूजा कुमारी पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएंगी और महिलाओं को हक की लड़ाई लड़ेंगी। इस अवसर पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता चंदन बोस एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, एडवोकेट सेल के अध्यक्ष तेज सिंह वरुण भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पूजा कुमारी, ने कहा कि 27 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा द्वारा राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर अत्यंत सम्मानित और विनम्र महसूस कर रही हूं। यह नियुक्ति बृजमोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली की अनुशंसा पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में की गई है।



जीएसटी में बदलाव देश की अर्थव्यस्था में मील का पत्थर साबित होंगे : मुख्यमंत्री

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी कार्डिसिल के नए सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाले हैं और आने वाले वर्षों में यह मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी को पूरी तरह से शून्य करने को भी एक ऐतिहासिक कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के नागरिक इन सुधारों का हृदय से स्वागत करते हैं। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन निर्णयों से आम नागरिक को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब हर नागरिक स्वतंत्र रूप से अपना जीवन बीमा ले सकेगा, अपनी जिंदगी को मूल्य दे सकेगा। यह कदम न केवल आर्थिक सुरक्षा देगा बल्कि सामाजिक न्याय



यह कदम न केवल आर्थिक सुरक्षा देगा, बल्कि सामाजिक न्याय को भी सशक्त करेगा : रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री

को भी सशक्त करेगा। शिक्षा क्षेत्र में राहत की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी खत्म करना विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा सस्ती और सुलभ होगी तथा हर बच्चा बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकेगा। नए बदलावों में देश के

हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा पर दी गई जीएसटी छूट से देश और दिल्ली दोनों को व्यापक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लंबे समय से सौर ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों में है और यह निर्णय उन प्रयासों को नई गति देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्डिसिल की बैठक में प्रत्येक बिंदु पर गहन विचार-विमर्श के बाद जो फैसले लिए गए, वे न केवल दूरदर्शी हैं बल्कि देश की आर्थिक विकास यात्रा में बेहद मजबूत कदम साबित होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इस विषय को भी राजनीति से जोड़ रही है। यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि देश और नागरिकों के हित में उठाए गए इन कदमों का समर्थन करने का है।

पुलिस ने शातिर ऑटो लिफ्टर को पकड़ा, दो बाइक व चाकू बरामद

नई दिल्ली, 4 सितंबर (एजेंसियां)। दिल्ली पुलिस ने नंद नगरी थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की दो मोटरसाइकिलें और एक बटन वाला चाकू बरामद किया गया है। आरोपी का नाम अरुण उर्फ विकास उर्फ बिच्छी (25) है, जो नंद नगरी का ही रहने वाला है।

दरअसल, एसआई सुभाष और कॉन्स्टेबल जितेंद्र बुधवार को शाम लगभग 6 बजे इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक मुखबिर से सूचना मिली कि चौर खंबा रोड लाइट, डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास एक ऑटो लिफ्टर आने वाला है। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक युवक को



मोटरसाइकिल पर पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से एक बटनदार चाकू मिला। जांच में पाया गया कि आरोपी जिस मोटरसाइकिल (नंबर डीएल13एसबी5339) पर सवार था, वह थाना ज्योति नगर इलाके से चोरी की गई

■ आरोपी ने अपने अपराध कबूल कर अन्य वारदातों में शामिल होने की भी जानकारी दी

थी। आरोपी की निशानदेही पर शाहदरा से चोरी की गई एक और मोटरसाइकिल (नंबर डीएल12एसए9955) भी बरामद की गई। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने अपराध कबूल कर लिए और अन्य वारदातों में शामिल होने की भी जानकारी दी। पुलिस सत्यापन में यह भी सामने आया कि अरुण पहले ही चोरी और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े तीन मामलों में शामिल रह चुका है।

नंद नगरी थाने में आरोपी के खिलाफ



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ गाजियाबाद
(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: 647 / बीओए-टी/0 / 2025-26 दिनांक 04.09.2025

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से 04 कार्यों हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धी समस्त विवरण व शर्तें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdaghaziabad.in पर उपलब्ध हैं एवं UPLC की वेबसाइट <https://tender.up.nic.in> पर निविदा विधिकी तिथि में उपलब्ध होगी। सम्बन्धित निविदाओं को ई-निविदा आमंत्रण सूचना में उनके सम्मुख दर्शायी गयी तिथियों पर डाउनलोड व अपलोड किया जा सकता है एवं प्राप्त ई-निविदाओं को उनके सम्मुख दर्शायी गयी तिथियों पर खोला जायेगा। निविदा में कोई भी संशोधन /परिमार्जन / परिवर्तन व अतिरिक्त सूचनाओं को वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जायेगा। प्रगामी मुख्य अभियन्ता

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, G@Gda Ghaziabad w: gdagzb हेल्पलाईन नं: 0120-4418384 वाट्सएप : 9990988004,वेबसाइट : www.gdaghaziabad.in

एक उत्तर शहर हमारा संकल्प

उत्तर रेलवे	
खुली निविदा सूचना	
भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल इंजीनियर-ट्रेक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्य के लिए ई-टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है।	
1. कार्य का नाम: अनुपृची-A 30,000 टन मीटर, 65 मि.मी. गेज मशीन से क्रश की गई पत्थर की बोल्सर (बैलेस्ट) की आपूर्ति, स्टैकिंग तथा शकवस्ती (SSB) बैलेस्ट डिपो स्थित बैलेस्ट सब डिपो संख्या-1 पर रेलवे वेगानों में लोडिंग। (इसमें सभी लोड एवं लिफ्ट, जी.एस.टी., कर आदि सम्मिलित है, अतः किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा)। (निविदा संख्या NIT-10-25-26-WC)	
2. अनुमानित लागत	Rs. 3,60,24,900/-
3. घोरेहर राशि	Rs. 3,30,100/-
4. ई-निविदा करने का दिनांक और समय & ई-निविदा खुलने का दिनांक और समय: ई-निविदा करने का समय शुरू दिनांक 12/09/2025 को 15:00 बजे से निविदा खुलने का समय & ई-निविदा खुलने का दिनांक 26/09/2025 को 15:00 बजे तक।	
5. निविदा की वेबसाइट जहां निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है:	www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।
पत्र संख्या 128-बन्धु/ वं.मं.अधि./ सं/ निविदा-10-25-26-बन्धुप्री दिनांक:- 04/09/2025	2699/2025
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ	

उत्तर रेलवे

ई-नीलामी हेतु सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक / माल भाड़ा, दिल्ली डिवीजन, उत्तर रेलवे, रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2022 / टीसी(एफएम) / 10 / 04 दिनांक 13.06.2022 और रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2024/RS(G)/779/77(E3471089) दिनांक 13.08.2024, के अनुसार दिल्ली मंडल के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली निम्नलिखित ट्रेनों में एसएलआर कम्पार्टमेंट और पार्सल वान (राउंड ट्रिप के आधार पर) के स्थान को 02 वर्थ के पड़े पर देने के लिए आईआरडीपीएस के ई-नीलामी मॉड्यूल के माध्यम से बोलिया आमंत्रित की जाती है :

क्रम संख्या	ई-नीलामी की आरम्भ होने की तिथि तथा समय	एस्सेट्स जिनकी नीलामी की जानी है
1.	08.09.2025 को 10:30 बजे	01 LVP4 (24 tonnes) on round trip basis in each train - 12454/12453, 20408/20407
2.	09.09.2025 को 10:30 बजे	12034 (F1), 12457 (F1, F2 & R1) 12820 (F1), 12874 (F1), 12963 (F1), 14164 (F1), 14507 (F1, F2, & R1), 14679 (F1), 14681 (F1, F2), 22222 (F1), 22429 (F1)
3.	10.09.2025 को 10:30 बजे	12005 (F1), 12011 (F1), 12013 (F1), 12017 (F1), 12040 (F1), 12057 (F1), 12191 (F1, F2), 12215(F1), 12455(F1), 12481 (F1), 12582(F1), 12826 (F1), 14053 (F2&R1) 22421 (F1, F2& R1)
4.	12.09.2025 को 10:30 बजे	12015 (F1), 12191(R1), 12428(F1), 12448(F1), 12482 (F1), 13258 (F1), 14087 (F1, F2 & R1), 14731 (F1), 20452 (F1), 20473 (F1, F2, R1), 22210 (F1), 22472 (F1, F2 & R1)

महत्वपूर्ण सूचना: ई-नीलामी के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलियादालों को नीचे दिए गए लिंक https://www.reps.gov.in/html/helpdesk/learning_centre.html (e-Auction leasing section) पर जाने की सलाह दी जाती है।

2. रेलवे प्रशासन किसी भी समय इन निविदाओं / अनुबंधों को समाप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार रखता है या इनके संबंध में किसी शोधार्थन अथवा अतिरिक्त नियमों और शर्तों के साथ इन निविदाओं अथवा अनुबंधों के बीच में ही समाप्त करने अथवा जारी रखने के संबंध में, जो की इन ट्रेनों के जारी रहने अथवा समाप्त होने की स्थिति पर निर्भर करता है।

2678/2025

आइए हमें मुस्कान के साथ



कैपिटल ज़ोन

2 हजार से ज्यादा लोगों ने यमुना में बढ़ता जल स्तर 3800 लोग प्रभावित सड़क पर लिया आसरा

- **यमुना पुश्ता पर झुगियों में रहने को मजबूर**
- **लगातार बढ़ रहा पानी 2023 के मंजर की दिला रहा याद**

नोएडा। यमुना उफानी हुई है। जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया। हिंडन का पानी भी डूब क्षेत्र में बने छह गांव के पक्के कमानों के बेहद नजदीक आ गया। ऐसे में हिंडन नदी के आसपास से भी लोगों को आश्रय स्थल पहुंचाया जा रहा है। यमुना में बुधवार से तेजी से बढ़ती रही है। वर्तमान में जल स्तर 207.47 मीटर के आसपास है। दिल्ली के सभी बैराज खोले जा चुके हैं। कालिंदी कुंज बैराज खोले जाने से नोएडा, ग्रेटरनोएडा यमुना के डूब एरिया में यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ा। रात तक यहां मौजूद फार्म हाउस, खेत सभी डूब गए। 2000 हजार से ज्यादा लोग सड़क पर झुगी लगाकर रह रहे हैं। प्राधिकरण ने आठ



आश्रय स्थल बनाए है। इनमें खानपान की व्यवस्था भी की जा रही है। प्राधिकरण ने सेक्टर-135 और 150 के आसपास बख्तावरपुर, छपरोली, कौंडली, नंगली वाजिदपुर, नंगला नगली, झट्टा गांव के बारात घर में राहत शिविर बनवाए हैं। पुश्ते के किनारे एक अस्थाई टेंट भी बनाया जा रहा। सीईओ ने डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बाहर निकलने की अपील की।

पिछले 24 घंटे में एक लाख क्यूसेक से अधिक पानी बढ़ा है। दूसरी ओर, हिंडन का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। हिंडन में 201 मीटर यानी 6487 क्यूसेक पानी



बह रहा है, जबकि नदी में खतरे का निशान 205 मीटर है। दोनों ही नदियों में दो दिनों से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे यहां रहने वाले लोग अब पलायन करने के लिए मजबूर हैं। यहां यमुना और पुश्ता की तरफ सेक्टर-133, 134, 135, 168 के अलावा 150 से ज्यादा इलाके में डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बाहर ज्यादा फार्म हाउस डूब चुके हैं।

रामवती यमुना पुश्ता पर झुगी में थी। उन्होंने बताया कि 2023 में हम हमारा परिवार फंस गया था। लेकिन इस बार परिवार समेत पहले ही बाहर आ गए। करीब

दो लाख का नुकसान हुआ है। खड़ी गोभी, मक्का की फसल बर्बाद हो गई। पानी में सब बह गया। 2023 में भी ऐसा हुआ था। सब बह गया था। बार बार बाढ़ आने से हम परेशान हो चुके हैं। ये हालात रामवती नहीं बल्कि गुर्दा और दयावर्त और अन्य लोगों के भी हैं। जिन्होंने पुश्ता पर आसरा लिया है।

सेक्टरों में बढ़ सकती है मुसीबत

नोएडा के सेक्टरों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसकी वजह सिचाई नाला है। ये नाला नोएडा के समीप दिल्ली से आकर नोएडा के सेक्टर-11, 22, 39, 50 होते हुए सेक्टर-168 और यमुना में जाकर गिरता है। यमुना और नाले में पानी का लेवल स्थिर होने से पानी बैक फ्लोर मार रहा है। इस वजह से सेक्टर-168 पर बने रेगुलेटर के तीनों पैन्ल (गेट) बंद है। नोएडा का सारा सीवेज एसटीपी के जरिए इसी नाले और बरासाती नालियों का पानी भी इसी नाले से यमुना तक जाता है।

सार संक्षेप

सुरक्षार्कमी उपलब्ध कराने वाली कंपनी की एचआर प्रमुख को पूर्व कर्मी ने दी धमकी

नोएडा। सुरक्षार्कमी उपलब्ध कराने वाली कंपनी की एचआर प्रमुख को कंपनी का पूर्व कर्मचारी प्रताड़ित कर रहा है। जातिसूचक शब्द बोलकर फोन और मैसेज करके परेशान कर रहा है। पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-20 थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-99 में रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह सुरक्षार्कमी उपलब्ध कराने वाली प्राइवेट कंपनी में एचआर प्रमुख के पद पर पिछले तीन वर्षों से हैं। एक माह पहले कंपनी में फील्ड ऑफिसर के पद पर काम करने वाले ठूसतम को उसकी गलत हकतों के चलते निकाल दिया था। तब से अब तक आरोपी दिन-रात मैसेज और फोन करके परेशान करता है। फोन पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गाली-गलौज कर रहा है। आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता के मुताबिक, उनके पास इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

चिकित्सकों ने रोबोटिक सर्जरी करके निकाली 437 ग्राम की प्रोस्टेट

नोएडा। फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक दुर्लभ सर्जरी में सफलता मिली। डॉक्टरों ने रोबोट की मदद से सर्जरी करके 85 साल के एक बुजुर्ग की 437 ग्राम की प्रोस्टेट को सफलतापूर्वक निकालकर नई कामयाबी हासिल की है। यह उत्तर प्रदेश में रोबोट से प्रोस्टेट निकालने के सबसे बड़े मामलों में से एक है। मरीज को पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से पेशाब से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो रही थीं और उसे 10 साल पहले ही सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी। पिछले छह महीनों में उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। उसे निचले यूनिटी ट्रेट में गंभीर लक्षण (एल्यूटीएस), पेशाब करने में ठकावट, बार-बार पेशाब आना और तेजी से पेशाब आने का दावाव जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देने लगे थे। पिछले कई महीनों से, मरीज कैथेटर (पाइप) पर निर्भर हो गया था, जिससे उसकी जीवनशैली पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था।

नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों से लाखों की ठगी

नोएडा। यूरोपीय देशों में विभिन्न पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने सेक्टर-16 स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कुछ समय के लिए कार्यालय खोला। ठगी के बाद कार्यालय बंद करके भाग गए। दिल्ली निवासी पीड़ित की शिकायत पर फेज-वन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। त्रिलोकपुरी निवासी मुकेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह वाहन चालाने का काम करते हैं। विदेश में चालाने का काम करने की इच्छा है। अगस्त 2024 में विज्ञापन के माध्यम से नोएडा के सेक्टर-16 स्थित एशियन माइग्रेशन कंसल्टिंग सर्विस कंपनी में बात हुई थी। आठ अगस्त को वह कंपनी के कार्यालय पहुंचे। जहां उनकी मुलाकात कंपनी के निदेशक रोहित हांडा और हिमांशु हांडा से हुई। कंपनी के कार्यालय पर उन्होंने कर्मचारी सोनाली जैन और प्रेरणा से मिलवाया।

प्राधिकरण सीईओ ने छह सेक्टर का निरीक्षण कर दिए निर्देश

- **सेक्टर-93ए के पास एक्सप्रेस-वे पर पहुंच मार्ग को चौड़ा करने के निर्देश**
- **सेक्टर-168 में एक एम्प हाउस का निर्माण कराए जाने के निर्देश**

नोएडा, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने उप महाप्रबंधक सिविल विजय रावल और सर्फिल अधिकारियों के साथ सेक्टर-93, 135, 163, 164, 166, 168 हिंडन नदी पर निर्माणाधीन पुल व पहुंच मार्ग का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सेक्टर-93ए और सेक्टर-135 पंचशील अंडरपास के निकट बहुत दुर्गन्ध आ रही है। इस संबंध में जल, सीवर विभाग को दुर्गन्ध के कारणों का पता



लगाते हुए उसको जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। ताकि राहगीरों को असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सेक्टर-93ए के पास एक्सप्रेस-वे पर पहुंच मार्ग को चौड़ा करने के लिए कहा गया। सेक्टर-164 के निरीक्षण के दौरान रोड के कुछ कार्य लंबित पाए गए। इस संबंध में रोड के सभी लंबित कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने, सेक्टर-166,163 के रोड के प्लान को दोबारा प्लान करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त सेक्टर-166 के औद्योगिक भूखंडों को भी नियोजित करने के नियोजन विभाग को

समस्याओं को लेकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से किसान मिले

नोएडा, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। किसान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल किसानों एवं ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम से प्राधिकरण कार्यालय में मुलाकात की। किसानों के मांग इस प्रकार, आबादी जहां जैसी के आधार पर नियमित की जाए। भवन निमावती में संशोधन कर भवनों की ऊंचाई सीमा 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर की जाए। किसानों के 5 प्रतिशत भूखंड पर धारा 10 के नोटिस भेजे जा रहे का विरोध प्रकट किया जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम द्वारा आशवासन दिया की जब तक शासन से कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता तब कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोई भी नोटिस नहीं भेजा जाएगा।



जाए। 1997 से 2014 के बीच अधिग्रहण की गई जमीन के सापेक्ष 64.7 बड़ा हुआ मुआवजा व 10 प्रतिशत आवासीय भूखंड दिए जाए। गांव का विकास शहर की तर्ज पर होना चाहिए। किसानों के लिए डेरी फार्म योजना की स्कीम लाई जाए।

इस मौके पर महेश अवाना, मनोज चौहान, गौतम अवाना,वेद प्रभान, लीले प्रधान, इन्द्र यादव, हरि प्रधान, जगेश लोहिया आदि लोग मौजूद थे।

जीएसटी की दर कम करने से आम जनता व व्यापारियों को मिलेगी राहत

नोएडा, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल नोएडा के चेयरमैन व व्यापारी नेता नरेश कुच्छल ने कहा है कि केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जीएसटी के स्लैब एवं दरें कम करने से आम जनता को भारी राहत मिलेगी और उद्यमियों और व्यापारियों को अपना व्यापार करने में आसानी होगी। इससे उत्तरप्रदेश के ढाई करोड़ व्यापारी लाभान्वित होंगे। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री का आभार व्यक्त किया।

कुच्छल ने बताया कि परिवर्तित जीएसटी की दरें 22 सितम्बर नवरात्रि के दिन से देश में लागू हो जाएगी और जीएसटी के स्लैब और दरों में राहत देने से लगभग 250 से अधिक वस्तुएं सस्ती होंगी। इन दो स्लैब के अलावा वित्तमंत्री ने एक तीसरा स्लैब भी रखा है, जिसमें फास्ट फूड, पान मसाला, सिगरेट, गुटका, तम्बाकू उत्पाद, कैफ़ीन युक्त पेय पदार्थ, फलों के रस, गैर एल्कोहालिक पेय आदि वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की दरें रखी गई हैं। जिन वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की दरें रखी गयी वे आम जनमानस के उपयोग में नहीं आती हैं। इस बदलाव से आम लोगों की ज़िंदगी आसान और सरल होगी। इस बदलाव से युवा आदमी, किसान, मजदूर, कारोबारी, मध्य वर्ग, महिलाओं और ग्रामीणों को भारी लाभ होगा। विशेष रूप से छोटे व्यापारी और व्यवसायियों के लिए व्यापार करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों में भारी बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा। इन सुधारों में जो सबसे बड़ी राहत दी गयी है वो यह है कि अब 2500 रुपए के कपड़े, जूते और चमड़ा उत्पाद पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। जबकि पूर्व में 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत था। इस प्रकार खानपान की सैकड़ों वस्तु पर जीएसटी केवल 5 प्रतिशत लगेगी।

नोएडा में 3 बिल्डर से वसूले जाएंगे 353.41 करोड़



- **2009-10 में हुआ आवंटन, कोविड-19 का दिया लाभ**
- **आरसी के लिए डीएम को लिखा पत्र**

ने तीन बिल्डरों के खिलाफ आरसी जारी करने के लिए डीएम को पत्र लिखा है। इन तीन बिल्डर पर करीब 353.41 करोड़ का बकाया है। अमिताभ कांत की सिफारिश के तहत 25 प्रतिशत पैसा जमा करने के लिए कहा गया। ये पैसा भी तीनों बिल्डरों ने जमा नहीं किया। इन तीनों को कई बार नोटिस जारी किया गया। इसके बाद भी बकाया जमा नहीं किया गया। गुप हाउसिंग भूखंड संस्था जीएच-2 सेक्टर-78 महागुप रिचल स्टेट प्रालि को 18 अप्रैल 2010 को आवंटन किया गया। 18 मई 2010 को लीज डीड कराते हुए जमीन पर कब्जा दिया गया। बिल्डर को बकाया पैसा जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन बकाया पैसा जमा नहीं किया गया। यही नहीं शासनादेश के तहत 21 दिसम्बर 2023 को कोविड-19 का लाभ दिया गया। जिसके बाद कुल बकाया का 25 प्रतिशत जमा करने के लिए कहा गया। ये पैसा भी जमा नहीं

किया गया। आवंटि पर 31 अगस्त तक 116.96 करोड़ का बकाया है। गुप हाउसिंग भूखंड संस्था जीएच-1 सेक्टर-77 मैसर्स प्रतीक रियल्टर्स प्रालि को 31 मार्च 2010 को आवंटन किया गया। 26 मई 2010 को लीजडीड करते हुए जमीन पर कब्जा दिया गया। शासनादेश के तहत कोविड-19 का लाभ दिया और 25 प्रतिशत पैसा जमा करने के लिए कहा गया। 31अगस्त 2025 तक बिल्डर पर कुल 162.27 करोड़ रुपए बकाया हो गया। वसूली के लिए गुरुवार को डीएम गौतम बुद्ध नगर को पत्र भेजा गया। गुप हाउसिंग भूखंड संस्था जीएच-1 सेक्टर-120 प्रतीक रियल्टर्स प्रालि का 10 दिसम्बर 2009 को आवंटन किया गया। 7 जनवरी 2010 को लीज डीड की करते हुए जमीन का आवंटन किया गया। आवंटि को बकाया जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए। शासनादेश के तहत कोविड-19 का लाभ दिया गया। साथ ही कुल बकाया का 25 प्रतिशत पैसा जमा करने के लिए कहा गया। ये पैसा भी जमा नहीं किया गया। इस पर कुल 74.18 करोड़ का बकाया है। आरसी के लिए पत्र भेजा गया।

पथवृक्षारोपण के संबंध में सीईओ ने समीक्षा की

नोएडा। नोएडा में विभिन्न संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों को एडोपशन पर दिये गये ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल वर्ज, पथवृक्षारोपण के संबंध में सीईओ ने समीक्षा की। बैटक में आईडीमिया, डीएलएफ, अडानी कॉन्वेक्स, डीएस गुप, आरक्यूब, एडवांट, आर्ट ऑफ लिविंग, गिव मि ट्रीज (पीपल बाबा), सीएण्डएस एवं एनएसएल इंफ्राटेक कंपनीज एवं संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर नोएडा क्षेत्र में आईडीमिया, आरक्यूब, आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा सौन्दर्यकरण के अंतर्गत वृक्षारोपण आदि कराये गये कार्यों की सराहना एवं प्रशंसा की गई है एवं आगामी समय में सभी को मौसमी फूलों व अलंकृत पेड पौधों से साज सज्जा कराये जाने के निर्देश दिए। रोड साइड ग्रीन बेल्ट में जन सामान्य के लिए आकर्षक वॉकिंग ट्रैक, बेंचेस आदि रखे जाने के निर्देश दिए। कुछ संस्थाओं द्वारा एडोपशन पर दिए गए क्षेत्र में काफी समय बीत जाने पर भी अपने क्षेत्र में खास कार्य नहीं कराये जाने के संबंध में एक महीने के अंदर कार्य कराये जाने के लिए नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए गए।

जीडीए ने वैशाली में अवैध गौशाला ध्वस्त कर करोड़ों की भूमि कराई मुक्त

गाजियाबाद, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। जीडीए ने अभियान चलाकर जीडीए को भूमि पर अवैध रूप से चलाई जा रही गौशाला को ध्वस्त कर दिया। इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में है। गुरुवार को प्रभारी प्रवर्तन जोन-6 के नेतृत्व में भूखंड संख्या-308, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद पर निर्माणकारी सुभाष चन्द्र मनोज द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई व भूखंड संख्या-318, सेक्टर-3ए, वैशाली, गाजियाबाद पर निर्माणकर्ता विपुल रस्तोगी व अन्य द्वारा भवन की छत पर किए गए अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त सेक्टर-3 में जीडीए की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर गौशाला का संचालन किया जा रहा था, जिसे कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई के समय प्रवर्तन प्रभारी जोन-06, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्तागण, समस्त सुपरवाइजर स्टॉफ, प्राधिकरण सुशाकर्मी बल उपस्थित रहा।



प्रशासन ने तेज किए राहत-बचाव कार्य

शरणालय संचालित हैं। इस कार्य में कई तरह की रेस्क्यू टीमें लगी हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और फायर विभाग की कुल चार टीमें तैनात की गई हैं। बुधवार को एनडीआरएफ ने सेक्टर-151 और जेवर के झुप्पा गांव से 44 लोगों को निकाला, जबकि एसडीआरएफ ने 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पशुओं की सुरक्षा के लिए सेक्टर-135 ग्रीन



बेल्ट पर शिविर बनाया गया है, जहां अब तक 1471 गौवंश को रखा गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने छह मेडिकल टीमें शरणालयों में तैनात की हैं। यहां एंटी स्नेक वेनम सहित सभी ज़रूरी दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे नदी-नालों के किनारे न जाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम से संपर्क करें और विस्थापित लोग शरणालयों में ही रहें। पशुपालकों को भी मवेशियों को प्रशासन द्वारा बनाए गए शिविरों में भेजने की सलाह दी गई है।



{ संपादकीय }

नई दिल्ली, शुक्रवार 5 सितम्बर 2025

संस्थापक-सम्पादक : **स्व. माठाराम सुरजन**

जीएसटी सुधार या भूल सुधार

30 जून और 1 जुलाई 2017 की आधी रात को संसद भवन को बिजली की लड़ियों और फूलों से सजाया गया था। जगमगाती संसद में नरेन्द्र मोदी ने आर्थिक आजादी की घोषणा की और वो भी आधी रात को। मोडिया ने इसे हिंदुस्तान का ऐतिहासिक पल बताया था। मकसद साफ था कि नेहरूजी ने आधी रात को ही दुनिया के सामने देश की आजादी का ऐलान किया था, तो किसी भी तरह उनके समकक्ष आने के लिए नरेन्द्र मोदी ने संसद भवन का ही इस्तेमाल किया और वह भी आधी रात को। दरअसल 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) लागू हुई और इसमें वैट, सेवा टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे कई अप्रत्यक्ष टैक्स को एक साथ किया गया ।लेकिन जिस तरह नोटबंदी की असफलता देश के सामने आने में देर नहीं हुई।वैसे ही जीएसटी की कमियां भी व्यापारियों को परेशान करने लगीं और आम आदमी के लिए भी कई तरह से यह व्यवस्था मारक साबित हुई।

अब इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव के वादे किए थे। उनके हिसाब से यह जनता के लिए दीवाली का तोहफा होगा। लेकिन शायद बिहार चुनाव के कारण दीवाली से पहले ही जीएसटी में दरों में बदलाव किया गया है, जो इसी महीने 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को इसकी मंजूरी दे दी है। अब 12फीसदी और 28 फीसदी की कर स्लैब को खत्म कर दिया गया है। केवल दो स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी रहेंगे साथ ही सिगरेट, शराब, निजी नौका, हेलीकॉप्टर जैसे खास सामानों पर 40फीसदी की विशेष कर दर लागू की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, ‘यह सुधार आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग, और एमएनएमडी के लिए लाभकारी होंगे।’

मीडिया एक बार फिर चरणवंदन में लग चुका है। इसे मोदी का मास्टरस्ट्रोक जैसे शीर्षकों से पेश किया जा रहा है, जबकि असल में यह कांग्रेस की सलाह पर अमल है और अपनी गलती का सुधार है। 2017 से आम आदमी को रोजगार की जरूरतों से लेकर जीवनरक्षक दवाओं तक सब पर जीएसटी का भार सहना पड़ता था। अब सरकार इसे आम आदमी के लिए राहत बता रही है। राहुल गांधी 2017 से लेकर अब तक कई बार यह मांग कर चुके थे कि गरीबों, मध्यम वर्ग और एमएनएमडी आदि को ध्यान में रखकर कर की दरें लागू हों, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। दरअसल जीएसटी के कारण खाद, किताब, ट्रैक्टर, दवाई, पढ़ाई दूध-दही, आटा-अनाज, यहां तक कि बच्चों की पेन्सिल-किताबें, ऑक्सिजन, इश्योरेंस और अस्पताल के खर्च जैसी रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो गई थीं। देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगा, सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी थोपा था।

अब राहत देकर इसे जनता के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पर पेश किया जा रहा है। नए जीएसटी स्लैब के बाद अब कैंसर की जीवन रक्षक दवाओं पर अब शून्य दर से कर लगेगा। दूध, पनीर, स्नैक्स और ब्रेडसहित आम उपभोग की 175 वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। पनीर, छेना और पराठे सहित सभाी प्रकार की भारतीय रेडियों पर कर 5 प्रतिशत से घटकर शून्य हो जाएगा। बालों का तेल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, रसोई के सामान अब 5 प्रतिशत कर के दायरे में आएंगे। 33 जीवन रक्षक दवाइयां 12 प्रतिशत से शून्य कर के दायरे में आ जाएंगी। मानव निर्मित रेशे पर कर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और मानव निर्मित धागे पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा वफाजाल बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी वसूल जाता है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि बीमा कंपनियों से आप उपभोक्ता को कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि अपने नुकसान की भरपाई भी आखिर में कंपनियां ग्राहकों से ही वसूलेंगी। यही बात बाकी उत्पादों पर भी लागू होती है। एक बार कोई सामान महंगा बिकने लगे तो शापद ही कभी दाम कम होते हैं। इसलिए दीवाली से पहले जिन लोगों को यह लग रहा है कि सरकार से उनको वाकई तोहफा मिल गया तो वे अपनी खुशियां थाम कर रहें। नई दरें लागू होने के बाद देखें कि सामान सस्ता होता है या किसी और तरीके से कीमत बढ़ाई जा रही है।

वैसे भी इस सरकार का ट्रैक रिकार्ड उद्योगपतियों के साथ खड़े होने का है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने बताया है कि कुल जीएसटी का दो-तिहाई यानी 64फीसदी हिस्सा गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब से आता है, और अरबपतियों से केवल 3फीसदी जीएसटी वसूला जाता है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स की दर 30फीसदी से घटाकर 22फीसदी कर दी गई है। दरअसल एक देश एक टैक्स की बात करते हुए मोदी सरकार ने 0फीसदी, 5फीसदी, 12फीसदी, 18फीसदी, 28 फीसदी की दरों के साथ 0.25फीसदी, 1.5फीसदी, 3फीसदी और 6फीसदी की विशेष दरों वाली एक देश 9 टैक्स प्रणाली को लागू किया था। इस वजह से व्यापारियों को तकलीफ हो रही थी, उसके कुछ उदाहरण भी सामने आए थे। तमिलनाडु में एक व्यापारी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी तो उसे निमाला सीतारमण ने बलाव बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। सरकार की ज़िद और मनमानेपन का यह एक सबूत था। हालांकि जीएसटी को श्री मोदी अपने बड़ी सफलता की तरह पेश करते रहे, लेकिन उसमें बार-बार बदलाव से यह जाहिर था कि 140 करोड़ की आबादी को प्रभावित करने वाले इस फैसले पर ठीक से सोच-विचार भाजपा ने नहीं किया। इससे पहले 28 फ़रवरी 2005 को यूपीए सरकार ने लोक सभा में जीएसटी की औपचारिक घोषणा की थी। फिर 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जीएसटी बिल लेकर आए वब भाजपा के साथ गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही जीएसटी का घोर विरोध किया था। अब इसी जीएसटी को वे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि यह कांग्रेस के फैसले को दोहराने से ज्यादा कुछ नहीं है।

मत के सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा राज्यपालों और राष्ट्रपति को उनके पास भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित तीन महीने की समय-सीमा, जिसकी अब मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा पुनर्परीक्षा की जा रही है, लगातार अनिश्चित होती जा रही है।

यह मामला, जो मूल निर्णय के समय सुलझा हुआ प्रतीत हो सकता था, अब नाजुक होता जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई के माध्यम से व्यापक संवैधानिक सिद्धांत सामने आ रहे हैं।दो-न्यायाधीशों के निर्णय की स्थिरता अनिश्चित प्रतीत होती है, न केवल बड़ी पीठ के संदेह के कारण, बल्कि अप्रैल के निर्णय में निहित असुलताओं के कारण भी, जो अनपेक्षित परिणामों के द्वार खुले छोड़ देती हैं। दांव पर केवल विधायी प्रक्रियाओं की दक्षता ही नहीं, बल्कि संवैधानिक पाठ, न्यायिक रचनात्मकता और अनजाने में नए संवैधानिक मानदंडों के निर्माण के जोखिमों के बीच संतुलन भी है।

शुरू से ही, 8 अप्रैल के इस फैसले की कुछ हलकों में राज्यपालों द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोकें रखने की लगातार शिकायतों के समाधान के रूप में सराहना की गई। राज्यपालों और राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर निर्णय लेने के लिए अनिवार्य करने वाले इस आदेश को जवाबदेही बढ़ाने और कार्यपालिका की मनमानी को रोकने के रूप में देखा गया। हालांकि, इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रतीत होता था, लेकिन इसमें अपनाई गई विधि, जो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं, एक कठोर समय-सीमा लागू करना—समस्याओं से भरी थी।

यह राष्ट्रपति के संदर्भ पर विचार कर रही बड़ी पीठ ने पहले ही इस तनाव को चिह्नित कर दिया है और आगाह किया है कि समय-सीमा अनिवार्य करना वास्तव में संविधान में संशोधन के समान हो सकता है। यह तक इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है कि दस्तावेज के निर्माताओं ने, व्यापक बहस के बाद, संबंधित कार्यकारी प्रधिकारियों पर ऐसी सख्तियां लागू करने से जानबूझ कर परहेज किया था। इसके बजाय, उन्होंने दुरुपयोग को रोकने के लिए असाधारण मामलों में परंपराओं, राजनीतिक जिम्मेदारी और न्यायिक निगरानी पर भरोसा किया। एक निश्चित अवधि को संवैधानिक मौन मानने का प्रयास करके, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने शायद एक ऐसी सीमा पर कर दी है जिसे नेकनीयत न्यायिक नवाचार भी उचित नहीं ठहरा सकते।

बड़ी पीठ ने एक सूक्ष्म दृष्टिकोण व्यक्त किया है। यह असाधारण विचार के मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप की वैधता

सपनों को संवारने वाला शिल्पकार: शिक्षक

तिवर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर विचारों की छलछलती सोच कुछ नया लिखने की प्रेरणा प्रदान करती महसूस की जाती है। मैं अपने शिक्षकीय अनुभव पर कुछ लिखूँ या फिर मेरे अपने गुरुओं की महिमा का गान करूँ, समझ पाने में असमर्थ हूँ। कभी यह विचार भी मन में उठने लगते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके चलते आज के कुछ शिक्षक इस महान पेशे को करलैकिक कर जाते हैं, क्या आज की समाजनजक वेतन प्रणाली ने ऐसे शिक्षकों के जीवन में अन्यायित आचरण का बीजारोपण किया है? आर्थिक संपन्नता के चलते ही कहीं शिक्षकीय पेशा अपने कर्तव्य से विमुख तो नहीं हो रहा है? ऐसे सवाल अंतर्मन में इसलिए हिलते मार रहे हैं कि आज से लगभग आधी शताब्दी पूर्व इस महत्वपूर्ण पेशे में संलग्न लोगों को मिलने वाला वेतन पारिवारिक जरूरतों के लिए अपर्याप्त था, किंतु शिक्षकों का आचरण वास्तव में गुरुओं की श्रेणी का हुआ करता

था।वर्तमान समय में कुछ लोगों के कारण इस पेशे में आई सामाजिक गिरावट ने यह सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या आज भी शालाओं को गुरुकुल का पर्याय माना जा सकता है? मेरी आत्मा से निकला उत्तर नकारात्मक जान पड़ता है ! शिक्षक दिवस के दिन इन बदली हुई परिस्थितियों में बहुत कुछ ऐसा लिखा जा सकता है जो भारतीय संस्कृति को नामावर गुजरता हो।

एक शिक्षक के रूप में इस सेवा को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को एक नहीं अनेक पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। अपनी छवि गुरु के रूप में स्थापित करने का सपना उसी दशा में पूरा हो सकता है, जब एक शिक्षक सबसे पहले अपने रहने और कपड़े पहनने के तरीकों का भलीभांति ध्यान रखें। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी एक शिक्षक अपनी कक्षा में प्रवेश करे, वह खुद को पूरे अनुशासन की परिधि में तौल ले। कारण यह कि हर विद्यार्थी अपने शिक्षक को अपना आदर्श मानसल है। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई विषय सामग्री बच्चों के मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव छोड़ती है। आगे चलकर यही शिक्षा एक अच्छे समाज के निर्माण में महती भूमिका निभती है। इसी कारण कहा जाता है— ०२१ शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है।' जब हम शिक्षक के रूप में एक अच्छे व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अपने जीवनकाल के सबसे अच्छे शिक्षक की तस्वीर घूमने लगती है। यह तस्वीर इसलिए हमारे सामने आती है, क्योंकि हमने उस शिक्षक से वह सब कुछ सीखा है जिसके चलते आज सम्मानजनक स्थान पर खड़े हैं। वहीं एक अच्छ शिक्षक माना जा सकता है, जो खुद को कुछ बोलने से पहले तौलता हो कि उसकी वाणी का प्रभाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक? एक शिक्षक का बेहतरीन व्यक्तित्व उसके बोलने के तरीके पर निर्भर करता है। एक शिक्षक का बेहतरीन वक्ता होना ही यह गुण है जिसके चलते उसके विद्यार्थी उसे पसंद करने लगते हैं। प्रत्येक शिक्षक को यह स्मरण रखना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों से बेहिर परे की बात न करे। ऐसे शिक्षक विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकते।

वर्तमान समय तेजी के साथ परिवर्तन के मार्ग पर अग्रसर है। आज के बच्चों का जीवन जीने का तरीका पहले की तुलना में पूरी तरह बदल चुका है। खास कर आज की किशोरीय और युवा पीढ़ी की सोच का अत्यन्त कर उन्हें शिक्षित करना बड़ी चुनौती है। वर्तमान पीढ़ी जिसमें युवक-युवती दोनों

को स्वीकार करता है, जहां सहमति न देना या निष्क्रियता स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक इच्छाशक्ति को नष्ट करती है। ऐसा हस्तक्षेप

उपचारात्मक है, जिसका उद्देश्य संवैधानिक विघटन के विशिष्ट उदाहरणों को संबोधित करना है। हालांकि, इस मामले में विशिष्ट उपाय को हर स्थिति में लागू होने वाले एक सार्वभौमिक नियम पर परिवर्तित करने से वैचारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इससे न्यायपालिका के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं को प्रभावों ढंग से पुनर्लेखन करके एक विधायी कार्य संभालने का जोखिम पैदा होता है। पीठ की आशंका है कि ऐसा दृष्टिकोण संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर सकता है, क्योंकि यह भविष्य में न्यायिक रूप से निर्धारित समय-सीमाओं को चुनौती देने वाले मुकदमों की संभावना को खुला छोड़ देता है, जिससे समाधान के बजाय अधिक अस्थिरता पैदा होती है।

इस अनिश्चितता के व्यावहारिक परिणाम दूरगामी हैं। यदि 8 अप्रैल का फैसला बरकरार रहता है, तो राज्यपालों और राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिससे पूर्वानुमानितता पैदा होगी और विधायी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। फिर भी, ऐसा करने से, यह उस विचार-विमर्श की गुंजाइश को भी कम कर देता है।

8 अप्रैल के फैसले में न्यायिक समीक्षा के अपने व्यवहार में भी असुलताएं हैं। इसने सही हो पुष्टि की कि विधेयकों को लंबित रखने में राज्यपाल का आचरण न्यायिक जांच से परे नहीं है। यह कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है कि कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी जवाबदेही से मुक्त नहीं है, खासकर जब निष्क्रियता प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमजोर करती है। फिर भी, यह निर्णय ऐसी समीक्षा के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में विफल रहा।

विशेष रूप से, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या जांच केवल आचरण तक ही सीमित है—अर्थात विलंब तक—या क्या यह विधेयकों के सार को भी शामिल कर सकती है। निर्णय यह सुझाव देता प्रतीत होता है कि एक बार जब किसी विधेयकों को निर्धारित अवधि बीत जाने के कारण स्वतः स्वीकृति मिल जाती है, तो राज्यपाल की पूर्व निष्क्रियता को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन क्या इससे संबंधित विधेयकों की विषयवस्तु

ही शामिल हैं, उन्हें किसी काम में किसी अन्य का हस्तक्षेप बर्दास्त नहीं। फिर वह उनके माता-पिता सहित शिक्षक के

■ **डॉ. सूर्यकांत मिश्रा**

क्यों न हों? ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों का कर्तव्य और अधिक बढ़ जाता है कि उनके विचारों में घुलमिल चुकी विषमता को कैसे बाहर निकालें? यदि एक शिक्षक ही व्यसन के कुपुल में पड़कर अपनी कक्षाओं में प्रवेश करेगा तो क्या वह आगे में थो डालने देना नहीं होगा? तब हमें विचार करना होगा कि हम डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उच्च विचारों को अपने हृदय में कैसे स्थान प्रदान करें? एक अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि एक अध्यापक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। प्रत्येक शिक्षक इस बात को जानता है कि उसका काम न केवल छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार भी करना है। तब वर्तमान का शिक्षक खुद को एक ऐसा उपकरण क्यों नहीं मान रहा है, जो उच्च स्तरीय वस्तुओं का उत्पादन कर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में सक्षम रहता है। आज एक शिक्षक की चुनौती पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। कारण यह कि अब जमाना ‘गूगल’ का है ! हर छात्र गूगल और किताबों

एक सच्चा शिक्षक अपनी महानता से आपको प्रभावित नहीं करना चाहता बल्कि वह आपको यह एहसास कराना चाहता है कि आपके पास स्वयं को खोजने का कौशल है। हमारे राष्ट्रनिर्माता को यह याद रखना होगा कि एक प्रतिभाशाली शिक्षक न केवल आज के बच्चे की जरूरतों को पूरा करने वाला माध्यम है बल्कि हर बच्चे के भविष्य में आशाओं और सपनों को संवारने वाला बड़ा शिल्पकार भी है।

के माध्यम से अपने ज्ञान को अपडेट करता रहता है। तब एक शिक्षक को हर परिस्थिति में अपने विद्यार्थियों के सवालों का सटीक जवाब देने खुद को अपडेट करना होगा।

‘शिक्षक ही शिक्षा व्यवस्था का हृदय है।’ उसके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से ही जीवन प्रकाशवान हो सकता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि अब शिक्षक का कार्य बोर्ड पर दो चाँक लेकर खड़ा होना ही नहीं रह गया है बल्कि अपने विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से वह सब कुछ प्रदान करना है जिसकी उम्मीद एक शिक्षक के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी चाहती है। समाज निर्माण की भूमिका में आज तैनात समस्त शिक्षकों को यह समझ लेना चाहिए कि ‘एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक’ पूरी दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। वास्तव में कहा जाए तो आज जरूरत इस बात की है कि एक अध्यापक खुद को केवल शिक्षक नहीं बल्कि यह मानकर काम करे कि वह जागरूकता पैदा करने की बड़ी मशीन है। शिक्षकों का प्रभाव केवल कक्षा की चहार दीवारों तक ही नहीं उससे भी आगे भविष्य निर्माण तक विस्तृत है। हमारे देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम कहा करते थे- ‘शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है, जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। यदि लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखें तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा।’

एक सच्चा शिक्षक अपनी महानता से आपको प्रभावित नहीं करना चाहता बल्कि वह आपको यह एहसास कराना चाहता है कि आपके पास स्वयं को खोजने का कौशल है। हमारे राष्ट्र निर्माता को यह याद रखना होगा कि एक प्रतिभाशाली शिक्षक न केवल आज के बच्चे की जरूरतों को पूरा करने वाला माध्यम है बल्कि हर बच्चे के भविष्य में आशाओं और सपनों को संवारने वाला बड़ा शिक्षक भी है। साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक अच्छा शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों में आशा का बीज को सकता है। उनके अंदर अंकुरित हो रही कल्पना को प्रस्फुटित कर सकता है। एक शिक्षक ही विद्यार्थियों में सीखने के प्रति जीवन्ता और जुनून पैदा कर सकता है। इसी कारण शिक्षा को संजीवनी और शिक्षक को हनुमान कहा जाता है।

आपके पत्र

खतरनाक मौसम में भी स्कूल खुले क्यों?

दुनिया भर में आपदा और संकट के समय शिक्षा व्यवस्था पर अस्थायी रोक लगाना कोई नई बात नहीं है। कोरोना काल में महीनों तक स्कूल बंद रहे और वैकल्पिक माध्यमों से शिक्षा को आगे बढ़ाया गया। जब महाभारी के दौर में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि मानी गई, तो बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बची संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई जाती?

यहां तक ​​​​दिया जा सकता है कि पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए स्कूल बंद नहीं किए जा सकते। लेकिन क्या पढ़ाई का महत्व बच्चों और शिक्षकों की जान से बड़ा है? शिक्षा तभी सार्थक है जब छात्र और शिक्षक सुरक्षित हों। गीली और टूटती छतों के नीचे, पानी से भरे आंगनों में और बीमारी के खोफ में पढ़ाई करने का निर्णय शिक्षा नहीं, बल्कि मनबुरी और लापरवाही कलहाएगी।

दरअसल, अमली समस्या हमारी नीति और नीयत दोनों की है। जिन अधिकारियों को स्थानीय हालात देखकर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, वे केवल ऊपर से आए आदेशों का इंतजार करते रहते हैं। और ऊपर बैठे नीति-निर्माता आमतौर पर कागजी रिपोर्टों

और फाइलों के आधार पर निर्णय लेते हैं। नतीजा यह होता है कि जमीनी हालात और सरकारी आदेशों के बीच बड़ा अंतर रह जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि शिक्षा विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर एक स्पष्ट नीति बनाएं। इसमें यह तय हो कि किन परिस्थितियों में स्वतः स्कूल बंद माने जाएंगे। जैसे- जब किसी जिले में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी हो, जब लगातार बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त हो जाए, या जब भवनों की सुरक्षा संदिग्ध हो। इससे निचले स्तर के अधिकारी समय रहते फैसला ले सकेंगे और बच्चों की जोखिम से बचाया जा सकेगा।

इसके साथ-साथ स्कूल भवनों की नियमित मरम्मत और रखरखाव पर भी जोर दिया जाना चाहिए। हर बरसात में छत टपकना और दीवारें गिरना हमारी शिक्षा व्यवस्था की पील खोल देता है। यदि बच्चों के लिए सुरक्षित भवन तक उपलब्ध नहीं करा सकते तो फिर शिक्षा के अधिकार की बातें खोखली साबित होती हैं।

एक और पहलू पर ध्यान देना जरूरी है। जब सरकारें स्मार्ट क्लास’, ‘डिजिटल एजुकेशन’ और

■ **के रवींद्रन**

आश्रय और संवैधानिक वैधता की भी जांच करने का रास्ता खुलता है? यदि बिना किसी ठोस समीक्षा के स्वतः स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तो संभावना है कि संदिग्ध संवैधानिक योग्यता वाले विधेयकों की संबोधित जांच तो पारित हो सकेतें हैं। इसके विपरीत, यदि न्यायालय स्वयं विषयवस्तु की जांच में शामिल होते हैं, तो यह न्यायिक वीटो के समान हो सकता है, जो शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है।

इन विवादों को सुलझाने के लिए स्पष्ट संस्थागत रास्तों के अभाव से दुविधा और भी जटिल हो जाती है। संविधान में नियंत्रण और संतुलन की एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की गई है जहां राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, राज्य के विभागों में संवैधानिक औचित्य की रक्षा में एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, विधेयकों पर

जटिल संवैधानिक या नीतिगत प्रश्न उठाते हैं। दूसरी ओर, यदि वृहद पीठ द्वारा फैसले को खारिज कर दिया जाता है, तो अनिश्चितकालीन विचलन की यथास्थिति वापस आ जाएगी, जब तक कि संसद स्वयं समय-सीमा तय करने के लिए हस्तक्षेप न करे, जो एक राज्यपाल के प्रभाव को कमजोर करता है। किसी भी स्थिति में, गहरा सवाल अनुसुलझा रहता है: जब विधेयकों में देरी हो रही हो, तो न्यायिक समीक्षा का वैध दायरा क्या होना चाहिए? क्या न्यायपालिका केवल यह आकलन करने तक सीमित है कि क्या देरी अनुचित है, या क्या वह आगे बढ़कर विधेयकों की प्रकृति की जांच कर सकती है, जब तक कि स्वीकृति न मिल जाए?

अप्रैल के फैसले में स्पष्टता की कमी से मुकदमों की बाढ़ आने का खतरा है। उदाहरण के लिए, तीन महीने की राज्यपालीय चुप्पी के बाद स्वतः कानून बन जाने वाले किसी विधेयक को बाद में संवैधानिक कमजोरियों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तब अदालतों को न केवल स्वतः स्वीकृति तंत्र की वैधता पर, बल्कि स्वयं कानून की मूल संवैधानिकता पर भी निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा। यह दो-स्तरीय मुकदमेबाजी उस निश्चितता को प्रदान करने के बजाय जटिलता को परतें बढ़ाएगी जिसका दवाइ इस फैसले में किया गया था। यह राज्यपालों को रणनीतिक रूप से पीछे हटने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है, यह जानते हुए कि विवादास्पद विधेयक, एक बार स्वतः स्वीकृति मिलने के बाद, वैसे भी न्यायिक बाधाओं का सामना करेंगे। ऐसा परिणाम विरोधाभासी रूप से उसी समस्या को और मजबूत कर सकता है जिसका समाधान अप्रैल के फैसले में किया गया था।

बड़ी पीठ के समक्ष चल रही सुनवाई इन तनावों को दूर करने की कठिनाई को रेखांकित करती है। न्यायिक रचनात्मकता लंबे समय से भारतीय संवैधानिक कानून की एक पहचान रही है, मूल संरचना सिद्धांत से लेकर मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्याओं तक। फिर भी, व्याख्या और संशोधन के बीच एक रेखा: कुछ कितनी भी धुंधली क्यों न हो, रही है। 8 अप्रैल के फैसले पर बहस उस सीमा की नाजुकता को उजागर करती है। समय-सीमाएं निर्धारित करके, दो न्यायाधीशों की पीठ ने भले ही नेकनीयत से प्रयास किया हो, शायद हद पार कर दी हो। बड़ी पीठ का सतर्क दृष्टिकोण इस जागरूकता को दर्शाता है कि संवैधाािक मौन का सम्मान किया जाना चाहिए, भले ही वे कभी-कभी कार्पालिका के अवरोधों का सामना करें। न्यायिक आदेश के माध्यम से हर कमी को पूरा करने का जोखिम यह है कि संविधान धीरे-धीरे आधारभूत पद नहीं रह जाता और न्यायिक रूप से जोड़े गए खंडों का एक ढेर बन जाता है।



ललित सुरजन

की कलम से

जीएसटी : परेशानियों का अंबार

द इकॉनामिस्ट के इस अंक में भारत के वर्तमान परिदृश्य पर तीन लेख हैं। एक लेख में कहा गया है कि जीएसटी का स्वागत है, किंतु यह अनावश्यक रूप से जटिल और लालफीताशाही से ग्रस्त है जिसके कारण इसकी उपादेयता बहुत घट गई है।

घणिका यह भी कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही जोरदार प्रचार के साथ बहुत सी योजनाएं प्रारंभ कर दी हों, लेकिन इनमें से अनेक तो पहले से चली आ रही थीं। जीएसटी का प्रस्ताव भी पुराना था। पत्रिका नोट करती है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जिस व्यवस्थित रूप में कार्य होना चाहिए उसे नरेन्द्र मोदी करने में समर्थ प्रतीत नहीं होते। जीएसटी की चर्चा करते हुए द इकॉनामिस्ट का कहना है कि अब पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा फार्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा जीएसटी वाले अन्य देशों में जहां टैक्स की सिर्फ एक दर है वहां भारत में शून्य से लेकर अठ्ठइस तक दरे तय की गई हैं। इसके चलते सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में जो दो प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई थी वह अब शायद एक प्रतिशत भी न बढ़ पाए।

(देशबन्धु में 13 जुलाई 2017 को प्रकाशित)
https://latit.surjan.blogspot.com/2017/07/blog-post_12.html

मिलाद-उन-दबी आज

इस्लाम का संदेश कोई नया धर्म नहीं है। प्रथम मानव और प्रथम पैगम्बर हज़त आदम से लेकर नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा (अलैहिमुस्सलाम) तक सभी दूतों ने एक ही शिक्षा दी—एक ईश्वर की उपासना और मानवता की सेवा। पैगम्बर मुहम्मद उसी परम्परा के अंतिम दूत हैं, जिन्होंने इस सत्य को पुनः स्थापित किया और पूर्णता प्रदान की।

पैगम्बर मुहम्मद का जीवन चरित्र विश्व-इतिहास में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला जीवन है। उनका जीवन एक ऐसा आदर्श है, जो न केवल अपने समय में, बल्कि पिछले 14 सी वर्षों से निरन्तर पढ़ा, समझा और अपनाया जा रहा है। उनकी संरत (जीवनी) पर असंख्य भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए हैं। उनकी शिक्षा यह है कि श्रेष्ठता का आधार न जाति है, न वर्ण, न सम्पत्ति, अपितु केवल धर्मान्ध्र आचरण और उत्तम चरित्र है।

ईश्वर ने अपने अंतिम दूत, पैगम्बर मुहम्मद को समस्त संसार के लिए दया और करुणा का स्रोत बनाकर भेजा। क़ुरआन में कहा गया है—

और हमने तुम्हें केवल जागतों के लिए दया स्वरूप भेजा है। (सूर अंबिया: 107)

पैगम्बर ने सदैव न्याय को सर्वोपरि रखा। एक प्रसंग में एक यहूदी व्यक्ति मुक़दमे में विजयी हुआ क्योंकि सत्य उसी के पक्ष में था, जबकि विरोधी एक मुसलमान था। उन्होंने घोषणा की—

यदि मेरी पुत्री फ़ातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। (बुख़ारी)

यह शिक्षा देती है कि न्याय के सामने रिश्ते, जाति या धर्म का कोई मूल्य नहीं।

जब ताइफ़ नगर के लोगों ने पैगम्बर को पथरों से घायल कर दिया, तो स्वर्गदूत ने उन्हें दण्ड देने की अनुमति मांगी। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया: मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनकी संतति से सदाचारी लोग उत्पन्न हों।

इस घटना से स्पष्ट होता है कि पैगम्बर दया और क्षमा के प्रतीक थे। हज़ के अंतिम उपदेश में पैगम्बर ने मानव समानता की घोषणा की— किसी अरब को अजमी पर, किसी ग़ोर वर्ण को श्याम वर्ण पर कोई श्रेष्ठता नहीं, केवल धर्मान्ध्र ही श्रेष्ठता का आधार है।

यह संदेश विश्व-मानवता के लिए भाईचारे और समानता का शाशवत सिद्धान्त है।

पैगम्बर ने सदैव अनाथ, विधवा और निर्धन को सहायता पर बल दिया। उन्होंने कहा— सबसे उत्तम मनुष्य वह है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। (मुन्नद अहमद)

पैगम्बर ने पड़ोसी के अधिकार को आस्था का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा—

जिब्रील मुझे निरन्तर पड़ोसी के अधिकार की शिक्षा देते रहे, यहां तक कि मैंने सोचा वे पड़ोसी को वारिस बना देंगे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

वह व्यक्ति सच्चा विश्वासी नहीं जो स्वयं तो तृप्त हो और उसका पड़ोसी भूखा रहे। (मुन्नद अहमद)

पैगम्बर ने नारी को ईश्वर की अमानत बताया। अंतिम उपदेश में उन्होंने कहा—

हे लोगो ! स्त्रियों के विषय में ईश्वर से डरते रहो, क्योंकि तुमने उन्हें ईश्वर की अमानत स्वरूप ग्रहण किया है। उन्होंने यह भी कहा—

तुममें सबसे श्रेष्ठ वही है जो अपने परिवार के साथ श्रेष्ठ आचरण रखे, और मैं अपने परिवार के साथ सबसे श्रेष्ठ हूँ। (तिर्मिजी)

पैगम्बर ने अत्याचार को सबसे बड़ा पाप बताया—अत्याचार से बचो, क्योंकि अन्याय प्रलय के दिन अंधकार बनेगा।

अत्याचारित की प्रार्थना से बचो, क्योंकि उसके और ईश्वर के बीच कोई पदार्थ नहीं। (बुख़ारी, मुस्लिम) उन्होंने घोषणा की—

हे लोगो ! तुम्हारा रक्त, तुम्हारा जीवन और तुम्हारी मर्यादा- सब एक-दूसरे पर उसी प्रकार पवित्र है जैसे यह दिन, यह महीना और यह नगर पवित्र है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

आज आवश्यकता है कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि वे वास्तव में समस्त मानवता के लिए कदम पतित हैं।

—जुहत सुहेल पाशा

प्रादेशिकी

उत्तराखंड ने केंद्र से मांगा 5702 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज

■ **प्राकृतिक आपदा से लोक निर्माण विभाग और सार्वजनिक सड़कों को 1163.84 करोड़ का हुआ नुकसान**
■ **आपदा प्रबंधन सचिव ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा ज्ञापन**

देहरादून, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के तमाम हिस्सों में आपदा जैसी स्थिति हुई है। अगस्त महीने में उत्तरकाशी चमोली और पौड़ी जिले में प्राकृतिक आपदा की वजह से काफी अधिक नुकसान हुआ है। साथ ही प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति भी देखी जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में हुए नुकसान का आंकलन किया है। जिसके तहत प्रदेश के तमाम विभागों को इस प्राकृतिक आपदा की वजह से 1941.15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से 5702.15 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की है। इस संबंध में आपदा प्रबंधन सचिव ने गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा है।

आपदा प्रबंधन विभाग ने इस साल मानसून के दौरान विभागों को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति



और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की मांग की है। इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने अपर सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को मेमोरेंडम सौंपा है। जिससे प्राकृतिक आपदा की वजह से प्रदेश के तमाम विभागों के नुकसान की भरपाई करने के साथ ही भविष्य में होने वाले नुकसान से बचने के लिए बेहतर काम किए जा सके। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा इस साल प्राकृतिक आपदा से लोक निर्माण विभाग और सार्वजनिक सड़कों को 1163.84 करोड़, सिंचाई विभाग की परिसम्पत्तियों को लगभग

266.65 करोड़, ऊर्जा विभाग को 123.17 करोड़, स्वास्थ्य विभाग की परिसम्पत्तियों को 4.57 करोड़, विद्यालयी शिक्षा विभाग की परिसम्पत्तियों को 68.28 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग की परिसम्पत्तियों को 9.04 करोड़, मत्स्य विभाग को 2.55 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग को 65.50 करोड़, शहरी विकास को 04 करोड़, पशुपालन विभाग को 23.06 करोड़ समेत अन्य विभागीय परिसम्पत्तियों को 213.46 करोड़ का नुकसान हुआ है। यानि सभी राजकीय विभागों को करीब 1944.15 करोड़ की सीधे तौर पर क्षति हुई है। इन परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति में 1944.15 करोड़ के साथ-साथ परिसम्पत्तियों को बचाने और अनेक ऐसी परिसम्पत्तियां, मार्ग, आबादी वाले

होशियारपुर। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुरुवार को कहा कि राज्य हाल के वर्षों में सबसे गंभीर बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा है। उन्होंने होशियारपुर जिले के टांडा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री कटारिया ने पत्रकारों से कहा कि पंजाब हाल के दिनों में सबसे गंभीर बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 में भी बाढ़ आई थी, लेकिन इस बार स्थिति और भी गंभीर है। जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण, न केवल पौंग बांध से, बल्कि भाखड़ा और रणजीत सागर बांधों से भी बहुत अधिक पानी छोड़ना पड़ा। पौंग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण होशियारपुर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि बांध अधिकारियों के लिए पानी छोड़ना मजबूरी थी, लेकिन अब हर घंटे अलर्ट की व्यवस्था है ताकि लोगों को पहले से आगाह किया जा सके और अचानक आने वाले उफान से बचाया जा सके।

आपदा में रावी व ब्यास में भारी मात्रा में लकड़ियां बही, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया

शिमला, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। आपदा ग्रस्त हिमाचल में रावी व ब्यास में भारी मात्रा में लकड़ी के बहते देखे जाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। न्यायालय ने इस मामले में हिमाचल, केंद्र सरकार व कुछ अन्य राज्यों से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह पेड़ों के कटान का मामला लगता है। अदालत ने नदियों में बह रहे लकड़ी के वीडियो भी देखे तथा इसे गंभीर मामला बताते हुए तीन सप्ताह में केंद्र, हिमाचल व अन्य राज्यों से रिपोर्ट तलब की है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं के साथ साथ बीते दिनों भारी मात्रा में लकड़ी के ब्यास नदी में बह कर आने के बाद पंडोह डैम में जमा होने के मामले में एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने भी इसकी जांच की मांग की थी। गौरलवह है कि हिमाचल बीते तीन सालों से लगातार प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। आपदा राहत के मुद्दे पर तो प्रदेश में सियासत चरम पर है, मगर राहत के अलावा बीते जून माह में कुल्लू जिला के गडडा व सैंज बली में बादल फटने के बाद ब्यास में भारी मात्रा में लकड़ी बह कर



आई। बीते दो सितंबर को आपदा ग्रस्त चंबा जिला में भी रावी नदी में भारी मात्रा में लकड़ी तैरती हुई देखी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इन मामलों का संज्ञान लिया है। प्रदेश में ग्रीन फेलिंग पूरी तरह से बंद है। हरे पेड़ों के कटान पर रोक के बावजूद नदियों में भारी मात्रा में लकड़ी के लट्ठों के

■ **हिमाचल बीते तीन सालों से लगातार प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है**

तैरते देखा जाना स्वावल खड़े कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुन्नुक् ने मामले को गंभीरता को देखते हुए पंडोह में लकड़ी के लट्ठों के तैर कर पहुंचने के मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए थे। रावी के मामले में वन विभाग का कहना है कि यह लकड़ी भारी बारिश से उखड़ने के बाद नदी में पहुंची है।

प्रसव पीड़िता को हेली सेवा से पहुंचाया अस्पताल
रुद्रप्रयाग/देहरादून। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार प्रतिकूल मौसम के बाद जैसे ही बुधवार से मौसम ने राहत दी जिला प्रशासन ने हेली के माध्यम से बसुकेदार तहसील के प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाना पुनः शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं गुरुवार को मथ्यागर्वी (जखोली) से एक प्रसव पीड़िता (नाम-सुबिका) को हेलीकॉप्टर के जरिये सुरक्षित लाकर सीएचसी अगस्त्यमुनि में भर्ती कराया गया। समय पर कारवाई से महिला सकुशल है। पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति से तहसील बसुकेदार के बांगर क्षेत्र की आठ से 10 ग्राम पंचायत डुंगर, बड़ेश, जौला, ताल जामण, उछोला, बक्सौर, मथ्या, घंघासु, भुगतल, खोडू, स्यूर, किमाना, दानकोट, पाटियों, डाँगी, कुड़ी अदुली, भटवाड़ी, बकोला आदि जनपद मुख्यालय से पूरी तरह कट गए। सभी मोटर मार्ग और पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त होने से राहत पहुंचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती था। मुख्यमंत्री के निर्देशों और जिलाधिकारी प्रतीक जैन की प्रत्यक्ष निगरानी में हर प्रभावित व्यक्ति और परिवार तक राशन व दैनिक उपयोग की वस्तुएं पहुंचाने का कार्य निरंतर युद्ध स्तर पर जारी है।

उत्तराखंड के सभी जनपदों में खोले जाएंगे वृद्ध आश्रम

देहरादून, 4, सितम्बर (एजेंसियां)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था किये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान धनराशि 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया जाएगा। दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनानगर्त, कक्षा एक से कक्षा आठ तक के दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को समाप्त किया जाएगा। श्री धामी ने 'मुख्य सेवक संवाद' कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ संवाद के दौरान उक्त घोषणायें की। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग शायी अनुदान एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन को इस वित्तीय वर्ष की पांचवीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान किया। श्री धामी ने वरिष्ठ

नागरिक एवं दिव्यांगजनों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सबके आशीर्वाद से ही उन्हीं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संवाद के पीछे भी उनका यही मतव्य था कि वो सबकी समस्याओं, आवश्यकताओं को सीधे तौर पर जान सकें, जिससे उनके समाधान के लिए और अधिक ठोस कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार के स्तर पर नीतियां और योजनाएं तो बन जाती हैं, परन्तु उन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल पाता है, जब वे जमीनी स्तर तक पूरी तरहपंशित और ईमानदारी से पहुँचें। साथ ही, लाभार्थी भी ये महसूस करें कि सरकार ने उनकी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने का कार्य किया है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के निरंतर प्रयास किए जा रहें हैं।

सार संक्षेप

हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, परीक्षाएं रद्द

शिमला। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून में लगातार हो रही बारिश, बाढ़,और भूस्खलन की घटनाओं में जान-माल की व्यापक हानि हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 3 4 3 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 3 8 5 जानवर मारे गए हैं और लगभग 3 1 5 8 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार 1, 3 0 0 से अधिक घर पूरी तरह से जबकि 2, 3 3 1 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं लगभग 2 7, 0 0 0 हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई हैं। छह राष्ट्रीय राजमार्गों और एक चार लेन सड़क सहित बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान पहुंचा है। 1 2 8 0 से ज्यादा जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं और 2 8 0 9 से ज्यादा ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लगातार गिरते पत्थरों के कारण ब्राजी में राष्ट्रीय राजमार्ग-0 5 को बंद करना पड़ा।

राज्यपाल ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर दी शुभकामनाएं

चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल प्रो असीम कुमार घोष ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को हरियाणा और पूरे देश के शिक्षकों को हार्दिक बधायी और शुभकामनायें दीं। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक युवा मस्तिष्कों को ज्ञान, मूल्यों और बुद्धिमत्ता से पोषित कर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। उनका निस्वार्थ समर्पण न केवल छात्रों का भविष्य संवारता है, बल्कि एक मजबूत, समावेशी और प्रतिस्पर्धी समाज की नींव भी रखता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक हमेशा से भारत की विकास यात्रा के मार्गदर्शक रहे हैं और पीढ़ियों को राष्ट्र के लिए सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करते रहे हैं।

ओखलकांडा की लापता महिला का शव बरामद

नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के ओखलकांडा से तीन दिन पहले लापता महिला का शव गुप्चवार को हल्द्वानी के गौला नदी से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मामले के अनुसार ओखलकांडा के बसोटिया गांव निवासी तुलसी देवी (5 0) मंगलवार को घास लेने के लिए जंगल गई थी। इसके बाद महिला घर नहीं लौटी। ग्रामीणों ने खोजबीन की तो मृतका के चप्पल और दरती गौला नदी के किनारे मिले। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि महिला तेज बहाव की चपेट में आकर बह गयी है।

सुडोकू 7025 का हल

5	2	9	1	7	3	6	4	8
8	6	7	9	4	2	3	5	1
3	1	4	5	8	6	9	7	2
7	9	2	8	6	5	4	1	3
6	4	5	7	3	1	8	2	9
1	8	3	2	9	4	7	6	5
4	7	1	3	5	9	2	8	6
9	5	8	6	2	7	1	3	4
2	3	6	4	1	8	5	9	7

महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती रहेगी सरकार : धामी

■ **अमरनाथ तिवारी**

देहरादून, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के

- **सीएम ने 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार देकर किया सम्मानित**
- **33 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला सम्मान**

बिना विकास अधूरा है, इसलिए सरकार हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी और उनके सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्त्री शक्ति, तीलू रौतेली एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार और 33 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। सीएम धामी ने वीरगंगा तीलू रौतेली को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि



आपदा पीड़ितों के साथ सरकार

धामी ने कहा कि यह आयोजन पहले आठ अगस्त को होना था, लेकिन आपदा के कारण स्थगित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, और सरकार केंद्र के सहयोग से प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचा रही है।

उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में जिस अदम्य साहस और रणकौशल का परिचय दिया, वह उत्तराखंड की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तीलू रौतेली को 'उत्तराखंड की झांसी की रानी' कहना अतिशयोक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'नारी तू नारायणी' के मंत्र के साथ महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। 33 प्रतिशत आरक्षण, बेटी

बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथाओं के अंत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को हर स्तर पर सामाजिक और आर्थिक मजबूती प्रदान की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है और देश में पहली बार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

दो दिवसीय राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय प्राचार्य सम्मेलन 2025 का आयोजन

देहरादून, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आरआईएमसी) ने दो दिवसीय राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय (आरएमएस) प्राचार्य सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में देशभर के पांच राष्ट्रीय सैन्य विद्यालयों के प्रमुखों ने भाग लिया, जिनमें शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक स्तर पर सहयोग को सुदृढ़ करने पर गहन विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुखों में शामिल रहे, लेफ्टिनेंट कर्नल के. अनुप नायर (बेंगलुरु), वी. के. गंगवाल जैन (चौल), लेफ्टिनेंट कर्नल श्रद्धु (अजमेर), लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभा बिष्ट (बेलगाम), और लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा (धौलपुर)। कार्यक्रम की शुरुआत आरआईएमसी के कमांडेंट कर्नल राहुल अग्रवाल द्वारा अतिथियों के स्वागत और सम्मान के साथ हुई। इसके पश्चात आयोजित विभिन्न सत्रों में संकाय प्रमुखों ने शैक्षणिक उत्कृष्टता, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों, नवप्रवेशित बालिका कैडेटों के समावेश, और समग्र छात्र विकास जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां दीं। सम्मेलन में



बुनियादी ढांचे में नवाचार, शिक्षकों के प्रशिक्षण, और एनडीए परीक्षा परिणामों को बेहतर बनाने की रणनीतियों पर विशेष बल दिया गया। आरआईएमसी और आरएमएस दोनों के नेतृत्व ने आपसी सहयोग और संसाधनों के साझा उपयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। सम्मेलन का समापन भविष्य की संयुक्त कार्ययोजनाओं के साथ हुआ, जिसमें शैक्षणिक सहयोग, संस्थाओं के मध्य कैडेट और संकाय आदान-प्रदान, और संयुक्त अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव शामिल थे। यह सम्मेलन सशस्त्र बलों के प्रमुख फीडबैक संस्थानों के बीच समन्वय को एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ।

कांग्रेस उत्तराखंड में अपने संगठन को मजबूत करने पर कर रही काम

■ **अमरनाथ तिवारी**

देहरादून, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। कांग्रेस उत्तराखंड में अपने संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव बीएम

- **राष्ट्रीय सचिव बीएम संदीप कार्यकर्ता से ले रहे फीडबैक**

संदीप उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं। इसी क्रम में मसूरी पहुंचे संदीप ने बताया कि उन्हें 17 लोगों ने मिलकर सुझाव दिए। उत्तराखंड में संगठन को मजबूती के साथ संघर्ष करना होगा। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए संगठन का मजबूत होना जरूरी है। सत्ता से बाहर करने का पूरा प्रयास किया जायेगा। संदीप ने कहा कि बीजेपी मतदान का अधिकार छीनने का कार्य कर रही है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जायेगा।



देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संगठन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उत्तराखंड में जिला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बीएम संदीप ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर सरकार बनाने का कार्य भाजपा ने किया है। बीएम संदीप ने कहा कि वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान कांग्रेस का नहीं है, बल्कि अब जनता का अभियान बन गया जायेगा। संदीप ने कहा कि बीजेपी मतदान का अधिकार छीनने का कार्य कर रही है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जायेगा।

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी को पकड़ा है और बेंगलुरु के महादेव पुरा की विधानसभा सीट में एक लाख से अधिक फर्जी मतों को पकड़ा है। वहीं कांग्रेस के 65 लाख लोगों का मतदान का अधिकार छीनने का कार्य भाजपा ने किया है। बीएम संदीप ने कहा कि वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान कांग्रेस का नहीं है, बल्कि अब जनता का अभियान बन गया जायेगा। संदीप ने कहा कि बीजेपी मतदान का अधिकार छीनने का कार्य कर रही है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जायेगा।

राजाजी नेशनल पार्क से हटाए गए वन गुर्जरों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

नैनीताल, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से हटाए गए 228 वन गुर्जर परिवारों का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। इस मामले को वन गुर्जर इशाराद की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। जनहित याचिका में इन परिवारों के पुनर्वास के मामले को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय इस मामले में आगे सुवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राजाजी नेशनल पार्क में 228 वन गुर्जर परिवार रह रहे थे। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2013 में एक शासनादेश जारी कर इन परिवारों को पुनर्वासित करने का निर्णय लिया। पुनर्वास के लिए बकायदा शाह मंसूर नामक क्षेत्र में भूमि भी चयनित कर ली गई।

देवाल विकासखंड में युवा ब्लॉक प्रमुख व सदस्यों ने ली शपथ, गिनाई प्राथमिकताएं

चमोली, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। देवाल विकासखंड में युवा नेता तेजपाल रावत ने ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ ली। इस दौरान तेजपाल रावत ने कहा कि देवाल के विकास के लिए वो हरसम्भव प्रयास करेंगे। जिससे उनका क्षेत्र विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से देवाल में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आपदा से हुए नुकसान को भरपाई के लिए वे प्रयासरत रहेंगे। चमोली जनपद के देवाल विकासखंड में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रमेश चंद्र ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत को ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद देवाल विकासखंड के युवा ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत ने ज्येष्ठ प्रमुख पद पर दीपक सिंह और कनिष्ठ प्रमुख पद पर पिंकी देवी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में थराली



विधायक भूपालराम टट्टा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकात किया। नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों शपथ ग्रहण कार्यक्रम के तहत देवाल के कुल 20 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 19 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं देवाल विकासखंड के युवा ब्लॉक प्रमुख ने शपथ ग्रहण में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक भूपालराम टट्टा का शाल ओढ़ाकर सम्मानित करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। साथ ही खंड विकास अधिकारी जयदीप बैराण ने ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया।

हरियाणा में बनेंगे क्वालिटी पर खरे उतरने वाले प्रोडक्ट : अश्विनी वैष्णव

चंडीगढ़, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। हरियाणा सरकार की औद्योगिक नीति और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से आईएमटी सोहना में जापान की कंपनी एटीएल ने करीब तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर लिथियम आयन बैटरी निर्माण का एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस इकाई से पांच हजार से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा और प्रदेश की पहचान औद्योगिक क्षेत्र में नयी ऊँचाइयों तक पहुंचेगी। रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीरवार को एटीएल बैटरी टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नखीर सिंह, टीडीके ग्रुप से सैतो और शशिदा, विदेशी सहयोग सहाकर पवन चौधरी और आईसीडब्ल्यू से पंकज महेंद्र भी उपस्थित रहे। श्री वैष्णव ने कहा कि जापान की तरह हरियाणा में भी अब क्वालिटी आधारित प्रोडक्ट तैयार होंगे। आधुनिक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। राव नखीर सिंह ने इसे हरियाणा के औद्योगिक इतिहास का स्वर्णिम दिन बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक सहयोग का प्रतीक बन चुका है।

प्रादेशिकी

एसआरएम यूनिवर्सिटी वाले अपने ही जाल में फंसे

सरकार का कानूनी शिकंजा

गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज

अनधिकृत रूप से चला रहे थे विधि पाठ्यक्रम, छात्रों ने घेरा तो पुलिस ने की बर्बर पिटाई

■ रतिभानु त्रिपाठी

लखनऊ, 4 सितंबर (देशबन्धु)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शनकारी छात्रों की बर्बर तरीके से पिटाई श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के संचालकों को महंगी पड़ती दिखने लगी है। आखिरकार वह अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। पिटाई का मामला तूल पकड़ते ही सक्रिय हुई सरकार ने यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को देर रात यूनिवर्सिटी के खिलाफ बाराबंकी कोतवाली में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत निदोष छात्रों पर जिस पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, अब वही यूनिवर्सिटी वालों पर कड़ी कार्रवाई को मजबूर हो गई है। विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने एसआरएम यूनिवर्सिटी, देवा रोड, बाराबंकी में विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन का मुद्दा उठाया और इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी पर प्रदर्शन



किया लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने अपनी ताकत के बल पर छात्रों की बर्बर पिटाई करवाई। घायल छात्रों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिन्हें देखने प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक गए। कहा जाता है कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके पूरा मामला उनके संज्ञान में दिया। धर्मपाल सिंह चूंकि स्वयं विद्यार्थी परिषद की राजनीति करते हुए मौजूदा महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे हैं। इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को बुलाया और जांच कमेटी बनाते हुए 24 घंटे

भाजपा सरकार का रवैया तानाशाहीपूर्ण : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ईमानदार होनी चाहिए। भाषा और व्यवहार उचित होना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार का रवैया तानाशाहीपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीए की एकजुटता और बढ़ती ताकत से भाजपा डरी हुई है। पीडीए बड़ी ताकत है। जनता भाजपा को हटाने के लिए तैयार है। बीजेपी को सावधानी के साथ सत्ता से बाहर करना है। उसके किसी उकसावे में नहीं आना है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा धोखेबाज पार्टी है। भाजपा जनता को पिछले एक दशक से छल रही है। विपक्षी दलों और मतदाताओं के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करती है। भाजपा किसी की सगी नहीं है वह अपने को भी धोखा देने से बाज नहीं आती है।

न्याय पंचायत ततीना की बैठक सात को

मवाना, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। विकास खंड मवाना अंतर्गत गांव ततीना न्याय पंचायत की बैठक सात सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें मतस्य पालन समिति का गठन किया जाएगा। उक्त जानकारी देते न्याय पंचायत के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि न्याय पंचायत ततीना के अंतर्गत आने वाली ततीना, जंघेड़ी, अटोरा, बिराना खेड़की में मतस्य जीवी सरकारी समिति लिमिटेड की प्रथम बैठक सात सितंबर को ततीना में दोपहर दो बजे रामेश्वर के घेर में आयोजित की जाएगी। मतस्य पालक, मतस्य पालक कार्यकर्ता बैठक में प्रतिभाग करें।

गंगाजल का उतार-चढ़ाव जारी पलायन कर रहे परेशान ग्रामीण

■ गुरुवार को गंगा डिस्चार्ज 1.80 लाख तयुसेक

मवान/हस्तिनापुर, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। गंगा का जलस्तर एक बार फिर ग्रामीणों की मुसीबतों में इजाफा कर रहा है। नदी के पानी में हो रहे लगातार उतार-चढ़ाव के कारण खादर क्षेत्र के लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। गांव-गांव में पानी घुसने से खेत डूब गए हैं और कच्चे मकान जर्जर होने लगे हैं। गुरुवार को बिजनौर बेराज से करीब 1 लाख 80 हजार क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज चल रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर स्थिर न होने से उन्हें लगातार असुक्षा का सामना करना पड़ रहा है। बता दे कि अगस्त के पहले सप्ताह से गंगा नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के खेल चल रहा है।

की जा रही है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि मौके पर अब तक कोई ठोस मदद नहीं पहुंच सकी है। लोगों ने मांग की है कि तुरंत राहत सामग्री, नावों और सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था की जाए।

ठोस कदम उठाए प्रशासन तो त्रासदी से जल्द मिले राहत

गंगा किनारे बसे गांवों के लोगों की नींद हराम हो चुकी है। ग्रामीणों को डर है कि अगर पानी का डिस्चार्ज इसी तरह जारी रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं ताकि उन्हें इस बाढ़ की त्रासदी से राहत मिल सके।

तक्षशिला पब्लिक स्कूल में धूमधाम मनाया गया शिक्षक दिवस

मेरठ, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। कंकरखेड़ा स्थित तक्षशिला पब्लिक स्कूल मेरठ में शिक्षक दिवस बड़ी धूम-धाम से मनाया गया। सर्वप्रथम डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के छाया चित्र पर माल्यार्पण करते हुए विद्यालय के चेयरमैन डॉ. ओमपाल सिंह तथा प्राचार्य डॉ. प्रवीन कुमार पथरा ने दीप प्रज्ज्वलित किया। तत्पश्चात विद्यार्थियों द्वारा गुरु-शिष्य परम्परा, गुरु महिमा आदि पर आधारित गानांर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया। मुख्य प्रस्तुतियों में सरस्वती वन्दना, गुरु वन्दना, गुरु अमृतवाणी तथा सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में आदि मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहे। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के लिए किए गये सभी कार्यक्रमों को शिक्षकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के अन्त में विद्यालय के चेयरमैन डॉ. ओमपाल सिंह तथा प्रधानाचार्य डॉ. प्रवीन कुमार पथरा ने अपने संभाषण में बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की और प्रत्येक के जीवन में शिक्षकों के महत्व को समझते हुए बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सार संक्षेप

नो हेलमेट, नो पेट्रोल के दिए निर्देश

मेरठ। जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह ने बताया कि जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शासन के निर्देश के क्रम में परिवहन आयुक्त, उओप्र० के पत्र के द्वारा दिनांक ०1 सितम्बर 2०25 से 30 सितम्बर 2०25 तक ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

शराब ठेके के पास से बाइक उड़ाई

मवाना। तहसील के समीप स्थित देशी शराब ठेके पास से गुरुवार को बाइक साफ कर दी। पीड़ित ने थाने पहुंचकर घटना के संबंध में थाने पर तहरीर दी। नगर के मुहल्ला हीरालाल निवासी अरविंद चैहान पुत्र हरीशचंद्र चैहान ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि वह दोपहर बाइक पेंशन प्रो-डीएल 55बीएच-9१26 द्वारा तहसील की ओर गए थे। उन्होंने लगभग 12.4० बजे तहसील के समीप देशी ठेके के बराबर में बाइक लॉक करके किसी व्यक्ति से बात करने लगे। थोड़ी देर बाद ही समय करीब एक बजे देखा तो बाइक वहां पर नहीं थी। इधर-उधर काफी तलाश की, लेकिन बाइक वहां पर नहीं मिली।

यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम पर हुआ विस्तृत मंथन

मेरठ। स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय में गुरुवार को र्कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचावश् (पीओएसएच) विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रकोष्ठ, सरदार पटेल सुभारती लॉ कॉलेज तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), मेरठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों और छात्रों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून के प्रति जागरूक करना और एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक माहौल को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में न्यायपालिका, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कानून के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

सर्वलांस टीम गाजियाबाद की मवाना में अटोरा रोड पर दबिश

मवाना। सर्वलांस टीम गाजियाबाद ने गुरुवार को किसी मामले में नगर के मुहल्ला कल्याण सिंह अटोरा रोड निवासी मुस्लिम युवक को हिरासत में लेकर थाने पर घंटों पृच्छाछ की। टीम द्वारा देर शाम तक पृच्छाछ जारी थी। उक्त टीम ने गुरुवार को सर्वलांस टीम गाजियाबाद साइबर क्राइम संबंधी मामले में मवाना पहुंची और मुहल्ला कल्याण सिंह अटोरा रोड पर दबिश देकर फैजान पुत्र नफीस को हिरासत में लिया और थाने ले जाकर उससे घंटों को पृच्छाछ की। देर शाम तक पृच्छाछ का क्रम जारी था। टीम ने देर शाम तक थाने में डेरा डाले रखा। इस दौरान मीडिया को टीम छात्रों कोई जानकारी नहीं दी गई। इस बाबत पूछने पर थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि सर्वलांस टीम गाजियाबाद साइबर क्राइम संबंधी किसी मामले में युवक से पृच्छाछ कर रही है। इस बाबत थाने पर कोई जानकारी टीम द्वारा नहीं दी गई है।

सुभारती में कला और संस्कृति के उत्सव में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा

ऑपरेशन सिंदूर पर नुक्कड़ नाटक ने दर्शकों को झकझोरा

■ **मंच पर संदेश स्पंदन-2025 बना प्रतिभाओं का महाकुंभ**
■ **होनहार छात्रों ने मनवाया लोहा, रैंप पर फैशन, कैनवास पर बिखेरे रंग**



आकर्षण रहा फैशन शो, जिसका विषय ‘बॉलीवुड’। ‘भारतीय संस्कृति’ था। इस शो में 13 कॉलेजों के प्रतिभागियों ने रैंप पर जलवा बिखेरा, जिसका मूल्यांकन निर्णायक मंडल रश्मि अरोड़ा, राँबिन सारन और सुजल सैनी ने किया। रोमांचक मुकाबले में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एवं फैकल्टी ऑफ साइंस ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी ने द्वितीय और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ने तृतीय स्थान हासिल किया।

पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

द्वारा सुभारती विश्वविद्यालय की सर्वोत्तम प्रभाएं विषय पर आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता में मेरठ के प्रसिद्ध युवा फोटोग्राफर्स करण और जतिन ने निर्णायक की भूमिका निभाई, जिसमें हसन राजा (पॉलिटेक्निक) प्रथम, तुषार कुमार (मंडल रश्मि अरोड़ा, राँबिन सारन और सुजल सैनी ने किया। रोमांचक मुकाबले में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एवं फैकल्टी ऑफ साइंस ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी ने द्वितीय और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ने तृतीय स्थान हासिल किया।

प्रस्तुतियाँ दीं। इन प्रस्तुतियों का मूल्यांकन मनमोहन भल्ला, भरत भूषण शर्मा और सीमा समर ने किया। प्रतियोगिता में डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को प्रथम, डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज को द्वितीय, तथा केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस एवं ज्योतिराव फुले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथैरेपी को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान मिला। इसी सभागार में आयोजित मिमिक्री प्रतियोगिता ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, जिसमें ज्योतिराव फुले सुभारती

कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं

■ स्वामीनाथ शुक्ल

अमेठी, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के खिलाफ कांग्रेस के गढ़ अमेठी में भी महिलाओं का पारा आसमान पर है। जबकि अमेठी में कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा हैं। लेकिन हाथ में बेलन लेकर दसियों हजार महिलाएं सड़क पर उतर पड़ी थी। इस पर भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां का अपमान, सहन नहीं करेगा हिंदुस्तान। इसलिए दसियों हजार महिलाएं हाथ में बेलन लेकर सड़क पर उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के अपमान के खिलाफ गुस्सा को हाथ में बेलन लेकर दसियों हजार महिलाएं अमेठी की सड़कों पर थी। महिलाओं की पायलट नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष चंद्रमा देवी थी। चंद्रमा देवी राजेश मसाला की पत्नी हैं। इस पर चंद्रमा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां का अपमान करके पूरे देश की मां,बहन और बेटियों का अपमान किए है। जिससे मातृशक्ति हाथ में बेलन लेकर सड़क पर उतरी है। उन्होंने कहा कि मोदी ने महिलाओं को क्या नहीं दिए है। महिलाओं के लिए सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस के मंच से समस्त नारी समाज को गाली दिए हैं। जिससे देश की महिलाओं का पारा आसमान पर है। इसका खामियाजा कांग्रेस और आरजेडी दोनों को भुगतना पड़ेगा। महिलाएं सड़क पर नारेबाजी भी कर रही थी। नारी के सम्मान में, नारी है मैदान में, मातृशक्ति का अपमान,सहन नहीं करेगा हिंदुस्तान, दिवंगत मां का अपमान, कांग्रेस की यही पहचान, राहुल गांधी शर्म करो आदि नारे लगाए जा रहे थे। बारिश में भीगते हुए महिलाओं का समूह सड़कों पर था। महिलाओं की भारी संख्या देखकर पुलिस विभा जैन, चीफ प्रॉक्टर कृष्ण चंद, श्रृणग कुमार महिलाओं का प्रदर्शन बहुत संयमित था।

महावारी व हाइजिनक के प्रति सोच परिवर्तन पर कार्यशाला

मवाना, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। एस इंटर कालेज में गुरुवार को आयोजित कार्यशाला में सच्ची सहेली एम्बोआई फाउंडेशन नया संदेश की रफ से माहवारी के बारे में बताया गया और रूढ़िवादी सोच को भी दूर किया गया। पारुल मिश्रा प्रज्ञान शालिनी भारद्वाज ने बताया कि महावारी में लर्जुक्क्यों को कैसे हाजीनक का ध्यान रखना है। महावारी छुपाने की नहीं बल्कि इस पर सही जानकारी और बात करने की जरूरत है। महिला तथा पुरुष शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं कर्मचारी की कार्यशाला में प्रधानाचार्य डॉ मेयरज सिंह ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि आज के समय में रूढ़िवादी सोच तथा छात्रों के प्रति जागरूकता के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर एक नई पहल की है। जिससे शिक्षक-शिक्षिकाएं छात्र-छात्राओं को जागरूक कर सकेंगे तथा समाज में एक नया परिवर्तन लाया जा सकता है। आज के कार्यक्रम में कोऑर्डिटर अंजू सिंह, कोऑर्डिटर निष्ठा, कोर्डिनेटर निपेंद्र कुमार भटनागर, चीफ प्रॉक्टर विभा जैन, चीफ प्रॉक्टर कृष्ण चंद, श्रृणग कुमार आदि का विशेष सहयोग रहा।

द्वितीय चरण के पांच दिवसीय एफ.एल.एन.

प्रशिक्षण शिविर का समापन



कितौर, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। बृहस्पतिवार ब्लॉक संसाधन केंद्र माछरा के सभागार कक्ष में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत परिषदीय स्कूलों के अध्यापकों/शिक्षा मित्रों का बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान के लिए द्वितीय चरण में दो बेचो के पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम, डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज को द्वितीय, तथा केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस एवं ज्योतिराव फुले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथैरेपी को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान मिला। इसी सभागार में आयोजित मिमिक्री प्रतियोगिता ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, जिसमें ज्योतिराव फुले सुभारती

पचास शिक्षकों के दो बेच बनाकर उनको प्रशिक्षित किया गया। तृतीय चरण के दो बेचो का शुभारंभ सोमवार से प्रारंभ किया जाएगा। द्वितीय चरण के दोनों बेचो के अध्यापकों को प्रशिक्षित करते हुए कहा के बेसिक स्तर के साथ साथ रोजाना की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 पर विशेष प्रकाश डाला गया तथा एनसीईआरटी की पुस्तकों के बारे में जानकारी दी गई प्रशिक्षण में पाठ योजना बनवाई गई तथा इसका प्रस्तुतिकरण भी कराया गया। इसका मूल्यांकन निर्णायक मंडल शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी के

निर्देशन व माछरा खण्ड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में कराया गया। इस दौरान मंजू दयाल विरासत अली, तसरीफ अली, ताहिरा खातून, मो.असद हयाती, मो.इरफान, अमरीश शर्मा कार्यालय सहायक, चारुशर्मा ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार, चांद मोहम्मद, जावेद अली, मो.इमरान, नसीम खानून, मो.इरफान, शालिनी, विकास कुमार, सुशीर कुमार, शमीम गौड, धर्मेन्द्र कुमार, शालिनी, ईतजार अली, सुशील कुमार, इरफान, वकार, शादाब, सुभाषिनी वर्मा आदि सैकड़ों अध्यापकगणों ने पांच दिवस प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया।

जलस्तर से त्रस्त ग्रामीणों का भाजपा मंत्री पर फूटा गुस्सा

■ **राज्य मंत्री के सामने जमकर फूटा गुस्सा, टुकड़ाई राहत सामग्री बोले राशन नहीं, जीवन और सुरक्षित ठिकाना चाहिए**
■ **ग्रामीणों ने जलशक्ति मंत्री के सामने किया हंगामा**



स्थान और स्थायी समाधान चाहिए। गंगा कटान से प्रभावित गांव में मंत्री दिनेश खटौक डीएम डॉ. वी.के. सिंह और एसएसपी विपिन ताड़ा के साथ पहुंचे थे। मंत्री ने आश्वासन दिया कि शासन और प्रशासन हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गंगा राहत सामग्री बांटी, ग्रामीण भड़क उठे। उन्होंने कहा कि राशन से कुछ दिन का गुजारा होगा, लेकिन जब घर ही बह जाएंगे तो कहा रहेंगे ग्रामीणों ने राहत सामग्री लौटाते हुए साफ कहा हमें राशन नहीं,

प्रशासन हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचा रहा है। कई परिवार पहले ही गांव छोड़कर सुरक्षित जगह जा चुके हैं, जबकि बाकी परिवारों का कहना है कि उनके पास पलायन का कोई विकल्प नहीं है। ग्रामीणों ने लौटाई राहत सामग्री जैसे ही अधिकारियों ने बाढ़ राहत सामग्री बांटी, ग्रामीण भड़क उठे। उन्होंने कहा कि राशन से कुछ दिन का गुजारा होगा, लेकिन जब घर ही बह जाएंगे तो कहा रहेंगे ग्रामीणों ने राहत सामग्री लौटाते हुए साफ कहा हमें राशन नहीं,

जीवन चाहिए।

हंगामा बढ़ते देख बैराज लौट जलशक्ति मंत्री

बाढ़ प्रभावित बस्तीरा गांव में राहत सामग्री लेने से इंकार करते हुए ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों द्वारा बढ़ते हंगामे और विरोध को देखते हुए मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी बिना राहत सामग्री बांटे ही लौट गए। घटनाक्रम से गांव में तनाव और असंतोष का माहौल बना रहा।

फ्रेंचाईजी मालिक देवेश कामरा ने किया जिम का दौरा

मेरठ, 4 सितम्बर (देशबन्धु)। आर.जी. डिग्री कॉलेज के निकट फिट-7 जिम में नई मशीनों की फिटिंग से लेकर रखरखाव को दुरुस्त किया जा रहा है। इस कार्य में अभी एक सप्ताह और लग सकता है। पुराने मैक्स को नई मशीनों का बेसबरी से इंतजार है। बता दें कि फिटनेस की दुनिया में महेंद्र सिंह धोनी ने करीब 10 वर्ष पूर्व एक खास पहल की थी। जिसकी देशभर में दर्जनों फ्रेंचाईजी खोली गई है। विगत 2015 में जनपद मेरठ के आर.जी. डिग्री कॉलेज के बराबर में निर्भय अकेड की तीसरी मंजिल पर एक फ्रेंचाईजी की शुरुआत की गई और मेरठ की जनता को बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए एक शानदार मंच मिला। जिम की शुरुआत के बाद से ही मशीनों का रखरखाव के करने के लिए विशेष टीम भी लगी है जो समय समय पर जिम इक्विपमेंट की देखरेख में लगी रहती है। बदलती टेक्नोलोजी के साथ अब तक कई मशीनों को रिप्लेस भी किया जा चुका है। इसी के मद्देनजर 2025 की दिवाली से पहले पूरे जिम को नया लुक मिलने जा रहा है। जिम के लुक को और



■ **दूसरे राज्यों से मंगवाई गई आधुनिक मशीनें**

सुगम बनाने के लिए फ्रेंचाईजी ऑनर देवेश कामरा ने जिम का दौरा कर मरम्मत से लेकर मशीनों के स्थान को चिन्हित किया। देवेश कामरा ने बताया कि इस बार जिम में कई मशीनें ऐसी देखने को मिलेंगी जो अभी तक दिल्ली के जिम तक भी नहीं पहुंची हैं। इन मशीनों से वर्कआउट करने में खास अनुभव तो मिलेगा ही साथ ही सेप्टी भी बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिन से मशीनों की फिटिंग कार्य चल रहा है। जिम के सभी इक्विपमेंट को बदला जाने में अभी एक सप्ताह का और समय लग सकता है। जिसके बारे में सभी मैक्स को सूचित कर दिया गया है।

खेल जगत्

एक व्यक्ति के तौर पर एमएस धोनी का व्यवहार मेरे लिए अहम : डेवाल्ड ब्रेविस

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभावान युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की एक क्रिकेटर के अलावा एक व्यक्ति के रूप में जमकर प्रशंसा की है। ब्रेविस ने कहा कि एमएस धोनी के बारे में मैं बस यही कह सकता हूँ कि उनकी विनम्रता और एक ईंसान के रूप में उनका व्यक्तित्व मेरे लिए सबसे खास रहा। मैदान के बाहर वह कैसे हैं, खिलाड़ियों और लोगों के लिए उनके पास कितना समय है। यह बेहद अहम है। उनके कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर वह सो रहे होते हैं, तो सिर्फ उसी समय दरवाजा बंद होता है। एबी डिविलियर्स के यूट्यूब चैनल पर गुरुवार को ब्रेविस ने कहा कि मैं कई बार उनके कमरे में गया, जहां उन्होंने क्रिकेट से इतर अपने शौक के बारे में चर्चा की। उनके साथ क्रिकेट देखना वाकई अद्भुत था। यह देखना भी अद्भुत था कि मैदान के बाहर वह क्या करते हैं।



हॉकी एशिया कप के सुपर-4 में भारत-कोरिया मैच हुआ ड्रॉ

अपने स्ट्रक्चर पर भरोसा कर अगले दोनों सुपर 4 मैचों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे : फुल्टन

■ **मूसलाधार बारिश के चलते करीब 50 मिनट देर से शुरू हुए मैच**

■ **सत्येन्द्र पाल सिंह राजगीर (बिहार), 4** सितम्बर (देशबन्धु)। स्ट्राइकर अभिषेक और सुखजीत सिंह के डी के भीतर रिवर्स हिट से गोल करने का मोह भारत को महंगा पड़ा। खासतौर पर अभिषेक ने मूसलाधार बारिश के चलते करीब 50 मिनट देर से शुरू हुए मैच हार्दिक के गोल से पहले क्वार्टर के अधबीच भारत ने बढ़त ली लेकिन अगले पांच मिनट में दो गोल खा 1-2 से पिछड़ गया। भारत ने खेल खत्म होने से सात मिनट पहले मनदीप सिंह के गोल से पांच बार के और मौजूदा चैम्पियन दक्षिण कोरिया के खिलाफ 12 वें पुरुष हॉकी एशिया कप में अपना पहला सुपर 4 मैच दो-दो से बराबर खेल अंक बांटे। भारत अब अपने दूसरे सुपर 4 मैच में चीन को 2-0 से आगाज करने वाली मलेशिया से भिड़ेगा। भारत के आक्रमण सेंटर



हाफ हार्दिक ने पांचवें मिनट में मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर दिलाया और इस पर मनप्रीत शॉट लिया लेकिन दक्षिण कोरिया के गोलरक्षक दीहान यंग ने अच्छा बचाव किया। अगले मिनट अभिषेक ने भारत को मैच का दूसरा पेनल्टी कॉर्नर दिलाया और इस पर दक्षिण कोरिया के गोलरक्षक दीहान ने रोकने की कोशिश की लेकिन इस पर लौटती गेंद को फिर गोलरक्षक ने रोक दिया। सुखजीत सिंह ने मैच के आठवें मिनट में दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी से गेंद छीनी और डी की ओर बढ़ते हार्दिक सिंह की ओर बढ़ना और तेज फर्राटा लगा आगे

बढ़ आए गोलरक्षक दीहान को छका गोल कर भारत को 1-0 से आगे कर दिया। चार मिनटमिन सियोन के स्लैप शॉट पर डी में जैसे ही सियोंग हो ने शॉट लेने की कोशिश की जुगराज ने पोछे से धक्का दे दिया इस पर लिए लिए रेफरल पर मिले पेनल्टी स्ट्रोक को जिहून यांग ने गोल कर दक्षिण कोरिया को एक एक की बराबरी दिला। पहला क्वार्टर खत्म होने एक मिनट पहले पेनल्टी कॉर्नर हियोनहांग किम ने गोल कर दक्षिण कोरिया को 2-1 की बढ़त दिला दी। हरमनप्रीत को मैच के 21वें मिनट में हरा कार्ड दिखा कर दो

अगले मैचों में अपने बेस्ट प्रदर्शन कर मौकों को भुनाना होगा : हरमनप्रीत

भारत के कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, 'हमारी टीम हमेशा खुद पर और मैं पेनल्टी कॉर्नर पर अपनी क्षमता पर भरोसा करता हूँ। दक्षिण कोरिया के फस्ट रशर ने पेनल्टी कॉर्नर पर ड्रैग फ्लिक बेहतरीन ढंग से रोके। हमें अब अगले मैचों में अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के साथ मौकों को पूरी तरह भुनाना होगा। हमने 1-2 से पिछड़ने के बाद तीसरे और चौथे क्वार्टर में गोल करने मौके भुनाए लेकिन आखिर में मनदीप सिंह के बराबरी दिलाते वाले गोल को छोड़ ज्यादा को भुना नहीं पाए।



मिनट के लिए मैदान से बाहर भेजा गया। दिलप्रीत सिंह और जुगराज सिंह ने डी के भीतर दक्षिण कोरियाई खिलाड़ियों की पहुंच से गेंद बाहर करने की बजाय ड्रिबल करने की कोशिश में गेंद गंवाई। अभिषेक, सुखजीत सिंह और मनदीप सिंह ने हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह के पास पर तीसरा क्वार्टर खत्म होने से पहले पहले पांच में तीन बार डी में पहुंचे लेकिन इन तीनों के निशाने परीत बराबर लक्ष्य चुकते रहे। खासतौर पर अभिषेक ने खुद के निशाने चूकते तीसरा क्वार्टर के पहले मैच

का चौथा पेनल्टी कॉर्नर दिलाया लेकिन इस पर भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह का निशाना लक्ष्य को चूका। स्ट्राइकर अभिषेक के रिवर्स स्ट्रिक से गोल करने का मोह भारत को भारी पड़ा। सुखजीत को रोकने पर भारत को मैच कु 54 वें मिनट में पांचवां पेनल्टी कॉर्नर लेकिन इस जुगराज सिंह के शॉट को गोलरक्षक दीहान यंग ने रोक कर बेकार कर दिया। सुखजीत के डी के भीतर पास पर मनदीप सिंह ने गोल कर भारत को दो दो की बराबरी दिला दी।

अमित मिश्रा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लिया

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। दिग्गज स्पिनर अमित मिश्रा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, आईपीएल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। 42 साल के मिश्रा ने गुरुवार को एक प्रेस रिलीज के माध्यम से संन्यास की घोषणा की। अमित मिश्रा ने कहा कि क्रिकेट में मेरे जीवन के 25 साल यादगार रहे हैं। मैं बीसीसीआई, हरियाणा क्रिकेट संघ, अपने साथियों, सहयोगी स्टाफ का इस दौरान साथ देने के लिए दिल से आभारी हूँ। मिश्रा ने लिखा, मैं प्रशंसकों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे प्यार और समर्थन दिया। क्रिकेट ने मुझे अनगिनत यादें दी हैं। मैं उन सभी को खोकर रखूंगा। हरियाणा की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले अमित मिश्रा ने 2003 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में डेब्यू किया था। 2008 में टेस्ट और 2010 में टी-20 में उन्होंने डेब्यू किया था।



क्रिकेट में मेरे जीवन के 25 साल यादगार रहे हैं। मैं बीसीसीआई, हरियाणा क्रिकेट संघ, अपने साथियों, सहयोगी स्टाफ का इस दौरान साथ देने के लिए दिल से आभारी हूँ : अमित मिश्रा

2017 के बाद से उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। अमित मिश्रा एक बेहतरीन लेग स्पिनर रहे हैं। 2003 से लेकर 2017 के बीच उन्होंने 22 टेस्ट में 76, 36 वनडे में 64 और 10 टी-20 में 16 विकेट लिए। मिश्रा निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज भी थे। टेस्ट में उनके नाम 4 अर्धशतक हैं। टेस्ट में उनका सर्वाधिक स्कोर 84 है। अमित मिश्रा का आईपीएल करियर भी लंबा रहा है।

अमित मिश्रा आईपीएल में तीन हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज लेग स्पिनर रहे अमित मिश्रा ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। वह आईपीएल में भी खेलते नजर नहीं आएंगे। मिश्रा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पर्याप्त मौके नहीं मिले, लेकिन आईपीएल का वह एक बड़ा चेहरा रहे हैं। 2008 से 2024 के बीच अलग-अलग टीमों का हिस्सा रहते हुए उन्होंने लीग के सफलतम गेंदबाजों में अपना नाम शुमार किया है। अमित मिश्रा 2008 से 2024 के बीच दिल्ली डेयरडेविल्स, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स और एलएसजी के लिए खेलें। इस दौरान मिश्रा ने 162 मैचों में 174 विकेट लिए। अमित मिश्रा आईपीएल इतिहास में तीन बार हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं।

सितारों से सजी यूपी योद्धाज की जीत की हैट्रिक पर नजरे

विशाखापट्टनम, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। यूपी योद्धाज प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) सीजन 12 में लगातार तीसरी जीत की तलाश में 5 सितंबर को रात 9 बजे विशाखापट्टनम के विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब में मौजूदा चैम्पियन हरियाणा स्टीलर्स से भिड़े। योद्धाज ने सीजन की शानदार शुरुआत करते हुए लगातार दो जीत दर्ज की हैं। पहले तेलुगु टाइटन्स और फिर पटना पाइरेट्स के खिलाफ जीत हासिल की योद्धाज ने। टीम फिलहाल अंकतालिका में चार अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। वहीं, हरियाणा स्टीलर्स आठवें स्थान पर हैं। हरियाणा ने अपने पिछले मुकाबले में यू मुम्बा को टाई-ब्रेकर में हराकर दो अंक जुटाए हैं। योद्धाज की उम्मीदें उनके अटेक और डिफेंस में आक्रामक के धुरंधरों-गगन गौड़ा और सुमित सांगवान-पर टिकी होंगी। गौड़ा अब तक दो मैचों में 21 रेड प्लॉइंड्स हासिल कर चुके हैं, जबकि कप्तान सांगवान ने अशु सिंह के साथ बेहतरीन तालमेल बिठाते हुए 13 टेकल प्लॉइंड्स जुटाए हैं। वहीं स्टीलर्स के लिए नवीन कुमार और विनय की जोड़ी ने यू मुम्बा के खिलाफ 17 अंक अर्जित किए थे। इस जोड़ी को रोकना योद्धाज के लिए जीत का अहम मंत्र साबित होगा। यूपी योद्धाज के सहायक कोच उषेंद्र मलिक ने मुकाबले से पहले कहा कि जब हम किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हैं, तो हमें अपनी टीम पर पूरा भरोसा होता है कि योजनाओं पर टिके रहकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।



एशिया कप : यूएई ने किया टीम का ऐलान

दुबई, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। एशिया कप के लिए यूएई ने टीम का ऐलान कर दिया है। 17 सदस्यीय टीम की कप्तान मुहम्मद वसीम को सौंपी गई है। टीम में तेज गेंदबाज मतिउल्लाह खान और बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत सिंह को शामिल किया गया है। मतिउल्लाह खान और सिमरनजीत सिंह के अलावा एशिया कप के लिए घोषित यूएई की टीम में वही खिलाड़ी शामिल हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही विक्रोणीय टी-20 सीरीज का हिस्सा हैं।

मतिउल्लाह ने अब तक यूएई के लिए एक वनडे और पांच टी-20 मैच खेले हैं। आखिरी बार इस साल जुलाई में पल ऑफ अफ्रीका सीरीज में नाइजीरिया के खिलाफ वह टी-20 मैच खेले थे। सिमरनजीत ने यूएई के लिए अब तक पांच वनडे और 11 टी-20 मैच खेले हैं। आखिरी बार दिसंबर 2024 में गल्फ टी-20 चैंपियनशिप के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह टी-20 खेले थे। यूएई ने आखिरी बार 2016 में बांग्लादेश में एशिया कप में खेला था। 2016 में एशिया कप पहली बार टी20



प्रारूप में खेला गया था। यूएई को भारत, ओमान और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। यूएई अपना पहला मैच 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत से खेलेगी। इसके बाद 15 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में ओमान से भिड़ेगी और फिर 17 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमों सुपर फोर चरण में पहुंचेंगी, जो 21 सितंबर से शुरू होगी। सुपर फोर चरण की शीर्ष दो टीमों 28 सितंबर को दुबई में होने वाले खिताबी मुकाबले में खेलेंगी।

लोरेंजो मुसेट्टी को हराकर सिनर सेमीफाइनल में

ओपन एरा में एक सीजन में चारों ग्रैंड स्लैम मुकाबलों के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए सिनर

न्यूयार्क, 4 सितम्बर (एजेंसियां)। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जैक सिनर ने बुधवार को यूएस ओपन में एक और लगभग बेदाग प्रदर्शन किया, जहाँ उन्होंने पहले इतालवी पुरुष मेजर क्वार्टर फाइनल में अपने हमवतन लोरेंजो मुसेट्टी को 6-1, 6-4, 6-2 से हराया। अलेक्जेंडर बुल्निको को चौथे दौर में हराने के बाद, सिनर ने मुसेट्टी को शानदार अंदाज में हराया और ओपन एरा में एक सीजन में चारों ग्रैंड स्लैम मुकाबलों के सेमीफाइनल में, पहुंचने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले 2008 में 22 साल के राफेल नडाल ने यह उपलब्धि हासिल की थी। सिनर ने अपनी दो घंटे की जीत के बाद मुसेट्टी के बारे में कहा कि हम एक-दूसरे को



बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम एक ही देश से हैं। हर बार ड्रॉ में हमारे कई इतालवी खिलाड़ी होते हैं। मुझे पता है कि यहां कई इतालवी खिलाड़ी हैं, इसलिए यहां खेलना अच्छा लगता है। जाहिर है डेविस कप और इस तरह के दूसरे मुकाबलों में साथ खेलने के कारण, हमें मैच के लिए दोस्ती को नजरअंदाज करना पड़ता है और फिर जब हम हाथ मिलाते हैं, तो सब कुछ

पुरुषों के हार्ड-कोर्ट स्लैम में सबसे लंबे जीत के सिलसिले
❖ रोजर फेडरर 40 (2005-08)
❖ नोवाक जोकोविच 27 (2011-12)
❖ जैक सिनर 26 (सक्रिय)
❖ नोवाक जोकोविच 26 (2015-16)
❖ इवान लेंडल 26 (1985-88)
❖ जॉन मैकेनरो 25 (1979-82)

ठीक रहता है। मेरे हिसाब से, यह एक शानदार प्रदर्शन था, बहुत ही ठोस। खासकर मैच की शुरुआत बहुत अच्छी रही। पिछले तीन हार्ड-कोर्ट मेजर

स्विचार्टेक को हराकर अमांडा अनिसिमोवा यूएस ओपन के सेमीफाइनल में

न्यूयार्क। अमांडा अनिसिमोवा ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे हुए विंबलडन चैंपियन इगा स्विचार्टेक को हराकर यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल में अमांडा अनिसिमोवा ने बड़ा उलटफेर करते हुए एक घंटा 38 मिनट तक चले मुकाबले में पोलैंड की स्तर टेनिस खिलाड़ी इगा स्विचार्टेक को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही अनिसिमोवा 53 दिन पहले विंबलडन फाइनल में मिली शर्मनाक हार का बदला भी ले लिया। अनिसिमोवा पहली बार यूएस ओपन सेमीफाइनल में पहुंची हैं जहां उनका सामना जापान की नाओमी ओसाका से होगा। मैच के बाद अनिसिमोवा ने कहा कि मैं सचमुच जरा भी डर के साथ मैदान पर नहीं उतरी थी। मैंने खुद को, और शायद दूसरों को भी, साबित कर दिया कि सकारात्मक सोच और जुझारूपन से अच्छे नतीजे जरूर मिलेंगे। स्विचार्टेक ने कहा कि मेरे लिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता। सब जानते हैं कि अमांडा कैसे खेल सकती है। उसे वहां संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज वह अधिक तेज थी। मेरी सर्विस ने मुझे निराश किया।

टूर्नामेंटों के विजेता, गत चैंपियन सिनर ने इन प्रतियोगिताओं में अपनी जीत का सिलसिला 26 मैचों तक बढ़ाया है - जिससे वह नोवाक जोकोविच और

इवान लेंडल के साथ तीसरे सबसे लंबे पुरुष हार्ड-कोर्ट मेजर जीत के सिलसिले की बराबरी पर आ गए हैं। एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 का

सम्मान बरकरार रखने के लिए फ्लशिंग मीडोज में अपने प्रतिद्वंद्वी कार्लोस अल्काराज से बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है।



सार संक्षेप

इंटरनेशनल लीग टी-20 के चौथे सीजन के शेड्यूल का हुआ ऐलान

नई दिल्ली। इंटरनेशनल लीग टी-20 (आईएलटी20) के चौथे सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। लीग का आगाज 2 दिसंबर 2025 को होगा जबकि समापन 4 जनवरी 2026 को होगा। टी-20 विश्व कप 2026 से टकराव से बचने के लिए पिछले सीजन की तुलना में इस बार आईएलटी-20 का शेड्यूल एक महीने पहले निर्धारित किया गया है। आईएलटी-20 2026 में कुल 34 मैच खेले जाएंगे। छह टीमें अबू धाबी नाइट राइडर्स, दुबई कैपिटल्स, गल्फ जायंट्स, डेजर्ट वाइपर्स, एमआई एमिरेट्स और शारजाह वॉरियर्स खिताब के लिए आमने-सामने होंगी। सभी मैच तीन स्टेडियम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी के जायदे क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। लीग स्टेज में 30 मैच होंगे, इसके बाद चार प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंगे। एलिमिनेटर और फाइनल दुबई में होंगे। क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 अबू धाबी और शारजाह में आयोजित किए जाएंगे। मुकाबले स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे) शुरू होंगे। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच होगा।

भारत की 12 सदस्यीय टीम विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप में भाग लेगी

नई दिल्ली। ओलंपियन दीपिका कुमारी और कंपाउंड स्टार ज्योति सुरेखा वेन्नम सहित 12 सदस्यीय भारतीय टीम शनिवार से कोरिया गणराज्य के ग्वांगजू में शुरू होने वाली विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप 2025 में भाग लेगी। कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित होने वाली इस चैम्पियनशिप के लिए भारतीय दल में ओलंपियन धीरज बोम्मादेवरा और अंकिता भक्त भी 12 सदस्यीय टीम में शामिल हैं। विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप पहली बार 1931 में आयोजित हुई थी। 1950 के दशक से प्रत्येक दो वर्ष में इसका आयोजन हो रहा है। भारतीय तीरंदाजों ने इस प्रतियोगिता में 15 पदक जीते हैं। जिनमें तीन स्वर्ण, नौ रजत और तीन कांस्य शामिल हैं। बर्लिन 2023 में आयोजित पिछले संस्करण में तीन स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक जीत कर भारत पहले स्थान पर रहा था।

राउंडग्लास हॉकी अकादमी ने तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया

मोहाली। राउंडग्लास हॉकी अकादमी ने भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र साई, सोनीपत को 3-1 से हराकर पंजाब हॉकी लीग (अंडर 21) के दूसरे संस्करण के चौथे दिन अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह लीग ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेला जा रही है। नामधारी हॉकी अकादमी ने निर्धारित समय में 1-1 से ड्रॉ के बाद एसजीपीसी हॉकी अकादमी, अमृतसर के खिलाफ शूटआउट में जीत हासिल कर बोनस अंक हासिल किया। राउंडग्लास हॉकी अकादमी ने पहले मिनट में गुरसेवक सिंह के गोल से बढ़त बनाई और 27वें मिनट में अमनदीप सिंह के पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके अपनी बढ़त दोगुनी कर दी।